संस्थापक : स्व . श्री वीर विक्रम आदित्य

हिन्द जनपथ

स्थापना वर्ष : 2002

पंचकूला
गुरुवार
5 नवंबर, 2026
वर्ष:25 अंक: 133
कुल पृष्ठ:08
मूल्य : 1 रुपया

खबरें छापते हैं छुपाते नहीं | दैनिक प्रभात संस्करण हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रकाशित। | www.hindjanpath.com

अपराध नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर डेटा आधारित रणनीति अपनाएं अधिकारी: डीजीपी अजय सिंघल



पेज-4

मोटी-मोटी बातें

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना से भारत की अन्य देश पर कम होगी निर्भरता - पीएम मोदी

नई दिल्ली। कैबिनेट की ओर से 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी देने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे भारत की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज ईवी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर भी, हम रिफाइन की गई सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं।



मौजूदा स्थिति को समाप्त करने के लिए कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दी है। पोस्ट में आगे कहा कि इस योजना की खासियत नए महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र, निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत सहायता, घरेलू स्तर पर अधिक मूल्य संवर्धन और मजबूत सप्लाई चेन है।

अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सिद्धांत स्पष्ट है... भारत के पास भविष्य की तकनीकें विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए !

कैबिनेट ने पांच वर्षों की अवधि के लिए 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 2,814 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव पर कंटेम्प्ट कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार की याचिका पर कल होगी सुनवाई

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) के बकाये के भुगतान के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव के खिलाफ 'आपराधिक अवमानना' (criminal contempt) की कार्यवाही शुरू की गई है।

पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष दलील दी कि यह मामला किसी भी तरह से 'आपराधिक अवमानना' का नहीं है।

सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार से लगभग 13,000 करोड़ रुपये का पुराना बकाया (legacy arrears) मिला है, और मुख्य सचिव को लगभग नियमित रूप से हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा रहा है। CJI ने सिंह से कहा कि इस याचिका को गुरुवार को एक दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो इसी तरह की एक अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही है।

8 अप्रैल को, हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बकाया भुगतान की योजना को रद्द कर दिया था और 30 जून तक सभी 'बकाये/लंबित किस्तों' का भुगतान IAS/IPS/IFS अधिकारियों पर लागू दरों के अनुसार करने का निर्देश दिया था। अपनी नई याचिका में, पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मुख्य सचिव से 30 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा गया था कि उनके खिलाफ 'आपराधिक अवमानना' की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

5 मिनट में साबित कर दूंगा कौन है देशद्रोही... राहुल गांधी की PM मोदी को दी बहस के लिए खुली चुनौती, अदाणी को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके उस आरोप पर खुली बहस की फिर से चुनौती दी, जिसमें कांग्रेस को 'देशद्रोही' कहा गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि वह पांच मिनट के भीतर यह साबित कर सकते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री ही इस 'टैग' के लिए फिट बैठते हैं। उन्होंने कहा, 'कहीं भी आइए, मेरे साथ बैठिए और बहस कीजिए। मैं पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि मोदी देशद्रोही हैं।'

अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत के मकसद से आयोजित कांग्रेस की 'इंसाफ रैली' को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के भाजपा के प्रस्ताव पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, 'वे कहते हैं कि संसद में चर्चा करें, लेकिन आप मेरा माइक बंद कर देते हैं; आप मुझे बोलने नहीं देते।''

मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित करने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष को बहस में शामिल होने की चुनौती दी थी। मोदी पर अरबपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'वह अदाणी के लिए काम करते हैं। वह पूरे देश की जमीन, बुनियादी ढांचा और हवाई अड्डे उन्हें सौंप देते हैं। वह किसानों के लिए काम नहीं करेंगे। वह छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए काम नहीं करेंगे; कांग्रेस करेगी।'

दो OTP और E-Sign से जमा होंगे दस्तावेज... वोटर ID बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, EC ने फॉर्म-6 और घोषणा पत्र की प्रक्रिया बदली

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे के अनुरूप, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया वाले राज्यों में नए मतदाता के पंजीकरण से जुड़े फॉर्म और उसके साथ संलग्न घोषणा पत्र को ऑनलाइन प्रक्रिया में अलग-अलग कर दिया है। आयोग ने सितंबर में उन राज्यों में अपने डिजिटल मंच से घोषणा पत्र को पहले ही हटा दिया था, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा हो चुका है।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक लोगों को फॉर्म-6 भरना होता है। बिहार में एसआईआर के बाद निर्वाचन आयोग ने इसके साथ एक घोषणा पत्र भी जोड़ दिया था, जिसमें फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों से उनके माता-पिता के एसआईआर संबंधी विवरण मांगे गए थे। हालांकि, ऑफलाइन प्रक्रिया में दोनों दस्तावेज अलग-अलग भरने होते हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में दोनों के लिए एक ही ओटीपी का इस्तेमाल किए जाने से यह सवाल उठने लगा था कि क्या आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय की मंजूरी के बिना फॉर्म-6 में बदलाव किया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 और पहले से इस्तेमाल किए जा रहे घोषणा पत्र को जमा करने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''पहले आवेदकों की सुविधा के लिए फॉर्म-6 और उसके साथ संलग्न घोषणा पत्र एक ही ओटीपी और ई-साइन के जरिए जमा किए जाते थे।

अग्निवीर योजना के चार साल के कार्यकाल में नहीं होगा बदलाव, मिलेगा लंबी सेवा का अवसर : सीडीएस

नई दिल्ली । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने स्पष्ट किया है कि अग्निपथ योजना जारी रहेगी। इसके तहत अग्निवीरों का मौजूदा चार साल का सेवा कार्यकाल जारी रहेगा। इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही चार साल की सेवा पूरी करने वाले उन अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा, जिनका पहले चरण में नियमित सैनिक के रूप में चयन नहीं हो पाता है। सीडीएस ने बताया कि दूसरी सेवा अवधि पूरी करने के बाद नियमित सैनिक के रूप में शामिल किए जाने वाले अग्निवीरों की वरिष्ठता पहले चयनित किए गए 25 प्रतिशत अग्निवीरों के बाद होगी। यह व्यवस्था योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के अनुरूप है। पहले चरण में नियमित सैनिक बने अग्निवीरों को वरिष्ठता में प्राथमिकता मिलेगी, जबकि बाद में चयनित होने वालों को उनके ठीक पीछे स्थान दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी सेवा अवधि पूरी करने के बाद अग्निवीरों के सामने सेवा जारी रखने या अपनी इच्छा से बाहर निकलने का विकल्प होगा। इस तरह उन्हें अपने भविष्य के बारे में फैसला करने का



अवसर मिलेगा।

सीडीएस के मुताबिक, यह व्यवस्था अग्निवीरों को अतिरिक्त अनुभव हासिल करने और सेना को अधिक अनुभवी जवान उपलब्ध कराने के लिहाज से फायदेमंद होगी। सीडीएस ने बताया कि दूसरी सेवा अवधि का उद्देश्य ऐसे अग्निवीरों को सेना में अधिक समय तक काम करने और अपना अनुभव, योग्यता तथा कौशल बढ़ाने का अवसर देना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले चार साल में नियमित सैनिक के रूप में चयन नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित अग्निवीर किसी तरह से कम योग्य हैं। चयन योग्यता और निर्धारित मानदंडों के आधार पर होती है। दूसरी सेवा अवधि उन्हें अपनी क्षमता साबित करने का एक और अवसर देगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अग्निवीरों को सेना में लंबे समय तक सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही, इस दौरान उनके नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का रास्ता भी खुला रहेगा। इससे अग्निवीरों और सेना दोनों को लाभ होगा। अग्निवीरों के वेतन और आर्थिक लाभों का उल्लेख करते हुए सीडीएस ने कहा कि पहले साल अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। विस्तारित सेवा के दूसरे साल में यह बढ़कर 43,500 रुपये और तीसरे साल 47,500 रुपये हो जाएगा।

अग्निवीरों के वेतन और आर्थिक लाभों का उल्लेख करते हुए सीडीएस ने कहा कि पहले साल अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरे साल यह बढ़कर 43,500 रुपये और तीसरे साल 47,500 रुपये हो जाएगा। उन्होंने इसे वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी बताया। सीडीएस ने कहा कि अग्निवीरों के योगदान का 70 प्रतिशत हिस्सा सरकार की ओर से जारी रखने की व्यवस्था भी है। दो साल की अतिरिक्त सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को मिलने वाला कुल आर्थिक पैकेज लगभग 10.92 लाख रुपये होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजादी की पहली लडाई (1857) का शहीद स्मारक का करेंगें लोकार्पण



हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई (1857) के शहीदों की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक के लोकार्पण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 5 नवंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस ऐतिहासिक स्मारक का लोकार्पण करेंगे और अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग अंबाला छावनी पहुंचेंगे, क्योंकि केन्द्रीय गृह मंत्री के विचार सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। श्री विज आज मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इसके उपरांत, श्री विज ने अंबाला छावनी के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और संबंधित अधिकारियों को आगामी 5 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

श्री विज ने कहा कि 5 नवंबर का दिन हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति देश की आजादी की पहली लड़ाई थी, जो कांग्रेस पार्टी के गठन से भी 28 वर्ष पहले लड़ी गई थी। दुर्भाग्यवश, इस ऐतिहासिक संग्राम और इसमें अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अनेक वीरों के योगदान को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे।

उन्होंने कहा कि अंबाला में निर्मित शहीद स्मारक देश का ऐसा पहला स्मारक है, जो विशेष रूप से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। इस स्मारक में 22 भव्य गैलरियों के माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उस दौर की लड़ाइयों, घटनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस स्मारक के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के उस इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जो अब तक व्यापक रूप से उजागर नहीं हो पाया था।

जनसमस्याओं की अनदेखी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में, गुरुग्राम में विभिन्न अधिकारियों पर लिया एक्शन

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान एक स्कूल के भवन के जीर्णोद्धार से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए दी।



बैठक में कुल 15 परिवाद सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि शेष 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में बेहतर, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका त्वरित एवं प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी क्षेत्र से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई करते हुए गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी के मामले को गंभीरता से लिया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के तोहफे का ऐलान

महंगाई भत्ता 2022 के 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत किया: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के तोहफे के रूप में महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे हमारी सरकार के कार्यकाल में महंगाई भत्ता 2022 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिसंबर के वेतनों और पेंशनों के साथ मिलेगा। इस ऐलान से पिछले दो महीनों में महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें अक्सर खजाना खाली होने का रोना रोती थीं, लेकिन हमारी सरकार ने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी और यह सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके जायज हक से वंचित रखने में वित्तीय मुश्किलों को बहाना नहीं बनाया जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'आज पंजाब के लगभग आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली के तोहफे के रूप में हमने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान



किया है। इससे डी.ए. बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है, जिससे कर्मचारियों को लगभग 3,988 करोड़ रुपये का सालाना वित्तीय लाभ मिलेगा। कर्मचारी हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं और हम उनकी भलाई, हक और सर्वांगीण कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिवाली की लाख-लाख बधाई।'

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सूबे के प्रशासन और लोक सेवा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के अतुलनीय योगदान को स्वीकार किया।

मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत, ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका

न्यूयॉर्क। अमेरिका के मतदाताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए नियंत्रण हासिल कर लिया। एनबीसी न्यूज के अनुमान के मुताबिक, 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स को 256 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत से 81 सीटें ज्यादा हैं। वहीं, 100 सदस्यीय सीनेट में उनके पास कम से कम 54 सीटें हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव अभियान के दौरान महंगाई कम करने और लोगों की जिंदगी को ज्यादा सस्ती और आसान बनाने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में लौटने के बाद उनका ध्यान दूसरी बड़ी योजनाओं पर चला गया। उन्होंने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' के नाम पर टैरिफ बढ़ाने, ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों और व्हाइट हाउस तथा वॉशिंगटन को नया रूप देने जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। आलोचकों का कहना है कि ये कदम उन वादों से अलग थे जो उन्होंने जनता से किए थे।



हार की खबरें आने के बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'मैं बैलेट पर नहीं था और अगर होता तो हम भारी बहुमत से जीतते।'

रिपब्लिकन पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ और प्रभाव को इस चुनाव नतीजे ने कमजोर कर दिया है। खास बात यह रही कि पार्टी को उन राज्यों में भी नुकसान हुआ जो लंबे समय से रिपब्लिकनों के गढ़ माने जाते थे, जैसे टेक्सास, कंसास और साउथ कैरोलाइना।

कंसास में एडम हैमिल्टन ने लगभग 95 साल पुराने रिपब्लिकन दबदबे को खत्म करते हुए सीनेट सीट जीती।

हिमाचल सरकार का एलान: 1,444 श्रमिक परिवारों को दिवाली पर 6.10 करोड़ की सौगात, सीएम वितरित करेंगे राशि

हिन्द जनपथ

शिमला (ब्यूरो)। हिमाचल प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को दिवाली के अवसर पर आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 नवंबर को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से यह राशि वितरित करेंगे। कुल 6,10,57,310 रुपये की यह सहायता 1,444 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को दी जाएगी। यह राशि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाएगी। इसमें विवाह सहायता योजना के लिए 1 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये शामिल हैं। शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 14 लाख 67 हजार 700 रुपये दिए जाएंगे। चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए 32 लाख 80 हजार रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 86 लाख 58 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।



शेष 5 लाख 10 हजार रुपये अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरित किए जाएंगे। यह सहायता श्रमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

हमीरपुर जिले के 148 लाभार्थियों को 64,94,610 रुपये मिलेंगे। चंबा के 50 लाभार्थियों को 14,12,600 रुपये दिए जाएंगे। सिरमौर के 29 लाभार्थियों को 15,38,200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मंडी जिले के 440 लाभार्थियों को सहायता मिलेगी। किन्नौर जिले के 168 लाभार्थियों को 64,92200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार का श्रमिक कल्याण पर जोर

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह, उपचार और आवास में सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना चाहती है। 6 नवंबर को वितरित होने वाली यह सहायता सरकार की श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है।

केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के इशारे पर 'आप' नेताओं के खिलाफ छापे मार कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा: भगवंत सिंह मान

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 'आप' नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की लगातार छापेमारी को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि भाजपा और उसकी एजेंसियां चाहे जितनी मर्जी छापेमारी कर लें, लेकिन कोई भी चीज 'आप' सरकार को पंजाब के लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करने से नहीं रोक सकती। 'आप' विधायक डॉ. अमनदीप कौर के घर हुई छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा कर रहे 'आप' नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि डराना-धमकाना, राजनीतिक बदला और साजिशें न तो 'आप' को कमजोर कर सकती हैं और न ही पंजाब के विकास के एजेंडे को पटरी से उतार सकती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार



को राजनीतिक बदले के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए।

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों की आवाज को चुप कराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये एजेंसियां अपने राजनीतिक मालिकों के इशारे पर छापेमारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इन्हें 'आप' नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी तनदेही से निभा रहे हैं।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'ऐसे हथकंडे न तो आम आदमी पार्टी को डरा सकते हैं और न ही पंजाब के लोगों की सेवा करने के प्रति हमारी वचनबद्धता को कमजोर कर सकते हैं। पंजाब के लोगों ने हमें बदलाव और विकास के लिए जनादेश दिया है और राजनीतिक धमकी का कोई भी हथियार इस मिशन को रोक नहीं सकता।' भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने की बजाय केंद्र सरकार को लोगों की मुश्किलें हल करने पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक साजिशें और दबाव की चालें हमें पंजाबियों से किए वादे पूरे करने से पीछे नहीं हटा सकतीं।' राजनीतिक रैलियों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राहुल गांधी सहित प्रत्येक राजनीतिक नेता रैलियां करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

राहुल गांधी अपनी विफलताओं के लिए भाजपा को ठहरा रहे जिम्मेदार: अनुराग ठाकुर

हमीरपुर। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राहुल गांधी की पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ता है तो वे लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित जनसंपर्क मार्च में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जनता के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय भ्रम पैदा करने और चुनावी प्रणाली में जनता के भरोसे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत संसदीय क्षेत्र-स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन से हुई, जिसमें राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए।

दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, देहरा, धर्मपुर और अन्य क्षेत्रों के कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस जनसंपर्क मार्च में हिस्सा लिया।

'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद बिहार और केरल में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए।

उन्होंने पूछा कि अगर ईवीएम आधारित चुनावों को लेकर कांग्रेस के आरोपों को सच मान लिया जाए तो क्या चुनावी हार के बाद केरल के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की उम्मीद की जाएगी?

उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह स्पष्ट करे कि क्या उसके आरोप सही हैं, या फिर कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों को चुनावी जनादेश का सम्मान करना चाहिए।

न्यूज डायरी

युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारियों को निष्कासित पर विरोध के स्वर मुखर

हिन्द जनपथ

शिमला : युवा कांग्रेस के 13 पदाधिकारियों को निष्कासित किए जाने के फैसले पर कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के 3 बार पूर्व प्रदेश महासचिव रहे सुक्रांत भाटिया ने इस फैसले पर कड़ा रोष जताते हुए इसे एकतरफा और अन्यायपूर्ण करार दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, भारतीय युवा कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी आलाकमान से फैसले पर पुनर्विचार कर निष्कासित कार्यकर्ताओं की बहाली की मांग की है। सुक्रांत भाटिया ने बुधवार को शिमला से जारी बयान में कहा कि जिन युवाओं ने विपरीत परिस्थितियों में लाठियां खाईं, सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया और संगठन को मजबूत करने के लिए दिन-रात मेहनत की, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं को बिना किसी ठोस आधार के बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह केवल कुछ पदाधिकारियों का निष्कासन नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की निष्ठा और समर्पण का अपमान है। उन्होंने कहा कि निष्कासित पदाधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। पार्टी और संगठन को जब भी आंदोलनों की जरूरत पड़ी, ये कार्यकर्ता हर मोर्चे पर आगे खड़े रहे। ऐसे में केवल दिल्ली नहीं पहुंच पाने को निष्कासन का आधार बनाना उचित नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियां होती हैं, जिन्हें नेतृत्व को समझना चाहिए। भाटिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीति ए.सी कमरों में बैठकर और तस्वीरें खिंचवाकर नहीं होती। असली राजनीति जनता के बीच रहकर, सड़कों पर संघर्ष करके और कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में साथ खड़े होकर होती है। यदि जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले युवाओं की लगातार अनदेखी की गई तो इससे संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से मांग की कि युवा कांग्रेस के निष्कासित पदाधिकारियों का निष्कासन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। आम परिवारों से आने वाले युवाओं को उनका सम्मान और अधिकार वापस मिले तथा एकतरफा फैसले लेने के बजाय कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए संवाद की प्रक्रिया शुरू की जाए।



बंडियां गांव में विधिक सेवा प्राधिकरण की मेगा ड्राइव का दूसरा चरण शुरू

धर्मशालाः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से बैजनाथ तहसील के बंडियां गांव में मेगा ड्राइव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि 29 अक्तूबर, 2026 से शुरू हुई यह 60 दिवसीय मेगा ड्राइव 28 दिसंबर, 2026 तक चलेगी। अभियान के तहत गांव के विभिन्न वार्डों में साप्ताहिक जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, कानूनी सहायता के प्रावधानों तथा पात्रता के आधार पर उपलब्ध कल्याणकारी सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के पात्र एवं जरूरतमंद वर्गों तक उनके घरद्वार पर पहुंचकर कानूनी सेवाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध करवाना भी अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने बंडियां गांव के निवासियों से अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध विधिक सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की।

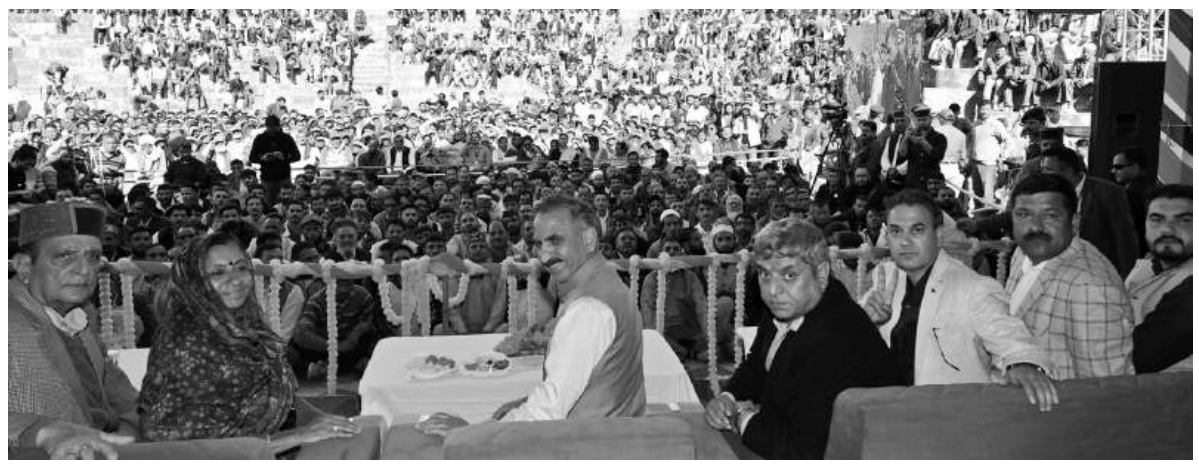
समयबद्ध पेंशन के लिए पात्र लाभार्थी बैंक व डाकघर बचत खाते आधार से जुड़वाएं

हिन्द जनपथ

शिमला (ब्यूरो)। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन माध्यम द्वारा लाभार्थियों के आधार से जुड़े (सीड) बैंक व डाकघर बचत खातों में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जिन पेंशनरों कों डाकघर व बैंक बचत खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वह खातों को आधार से जुड़वाकर पेंशन की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी इस योजना का अविलम्ब लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल व सितम्बर माह में नवीनतम छःमाही जीवन प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. एवं आय प्रमाण पत्र सहित चिकित्सा प्रमाण पत्र (जिसमें लाभार्थी का दीर्घकालीन उपचार लिखा हो) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने चंबा के चुराह में 60.67 करोड़ की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास



भूपिन्दर चौहान

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू में 60.67 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 विकासोत्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने भंजराड़ू में 2.84 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय भवन तीसा, 25.51 करोड़ रुपए की लागत से कियाणी-राजनगर-चकलू-कोटी सड़क के उन्नयन, 2.35 करोड़ रुपए की लागत से चुराह तहसील की ग्राम पंचायत सत्यास को राणिकोट नाला से पेयजल आपूर्ति योजना, 1.68 करोड़ रुपa की लागत से चुराह तहसील की ग्राम पंचायत करेर और चरौड़ी के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन एवं संवर्धन, 4.58 करोड़ रुपए की लागत से चुराह तहसील की ग्राम पंचायत भंजराड़ू और खुशनगरी के अंतर्गत गांव फुलतवास, सतलोगे-प् एवं प्प् तथा खुशनगरी की पेयजल योजना के लिए अतिरिक्त जल स्रोत उपलब्ध करवाने और 2.85 करोड़ रुपए की लागत से चुराह तहसील की ग्राम पंचायत घुलेई के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं के सुधार एवं संवर्धन कार्यों का लोकार्पण किया।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 8.27 करोड़ रुपये की लागत से गांव कैहला के लिए संपर्क सड़क, 5.64 करोड़ रुपए की लागत से गांव टिकरी के लिए संपर्क सड़क तथा 6.94 करोड़ रुपए की लागत से डकाला से कुंडा तक सड़क निर्माण कार्य की आधारशिलाएं भी रखीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकासात्मक परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के बेहतर संपर्क से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और चुराह क्षेत्र का सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं के माध्यम से संबंधित गांवों के लोगों को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए: राज्यपाल



भूपिन्दर चौहान

शिमला : राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज मंडी के सुन्दरनगर में समावेशी समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा और क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए समान अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

राज्यपाल आज स्पेशल ओलंपिक्स भारत, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित 'दीपावली उत्सव-2026 विशेष बच्चों की क्षमताओं का उत्सव' कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिमाचल प्रदेश के विशेष खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन पूरे प्रदेश और देश के लिए गौरव का विषय है। उनकी उपलब्धियां दृढ़ संकल्प, समावेशिता और उत्कृष्टता की सच्ची मिसाल हैं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में समावेशी विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि विकास की प्रक्रिया में कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। उन्होंने वर्ष 2015 में पहली बार विशेष ओलंपिक पदक विजेताओं को केंद्र सरकार की नकद पुरस्कार योजना में शामिल करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके खेल प्रदर्शन को उचित पहचान और सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में इस योजना में किए गए संशोधन से भी दिव्यांगजनों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अंतर-विभागीय बैठक आयोजित



हिन्द जनपथ

शिमला (ब्यूरो)। हिमाचल प्रदेश में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज एक अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई। प्रदेशभर में 60 दिनों तक चलाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को तंबाकू सेवन से रोकना तथा पहले से तंबाकू का सेवन कर रहे लोगों को इसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभियान के पिछले संस्करण में हिमाचल प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी स्थान मिला था।

बैठक में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विज्ञापनों के माध्यम से तंबाकू उत्पादों के बढ़ते प्रचार पर चिंता व्यक्त की गई। इस तरह का प्रचार युवाओं को तंबाकू सेवन के प्रयोग और धीरे-धीरे इसकी लत की ओर प्रेरित कर सकता है। ऐसे प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। अभियान के तहत तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने, तंबाकू मुक्त गांवों को प्रोत्साहित करने, कोटपा-2003 और पीईसीए-2019 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शैक्षणिक संस्थानों, सोशल मीडिया और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेशभर के लगभग 18 हजार शैक्षणिक संस्थानों को इस अभियान के दायरे में लाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों एवं कार्यस्थलों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाए रखने के निर्देश जारी किए जाएंगे। कार्यालय परिसरों में अनिवार्य रूप से तंबाकू निषेध संबंधी साइन बोर्ड लगाए जाएंगे तथा भवनों के प्रवेश द्वारों पर तंबाकू निपटान बॉक्स स्थापित किए जाएंगे।

राजस्थान को बिजली बेचने से प्रदेश को आगामी चार महीनों में 400 करोड़ रुपये की आमदनी होगी: मुख्यमंत्री

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के चार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरी, थल्ली, जज्जाकोठी तथा मारूंड को सीबीएसई से सम्बद्ध करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, चुराह में विभिन्न पंचायतों के लिए सड़क निर्माण के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की गई।

मुख्यमंत्री ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के भंजराड़ू कला मंच में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणाएं कीं।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अब राजस्थान को 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बेचने का समझौता किया है जिससे आगामी चार माह में प्रदेश को 400 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 180 मेगावाट की बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणामस्वरूप इसमें निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पुरजोर पैरवी की है। उन्होने कहा कि वाइल्ड फ्लॉवर हॉल शिमला का मामला वर्ष 2003 से लंबित था और इस मामले में प्रदेश सरकार ने प्रभावी कानूनी पैरवी करते हुए जीत हासिल की। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 401 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि अब ई-नीलामी के माध्यम से प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 37 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 23 वर्षों में इस संपत्ति से प्रदेश को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब इससे होने वाली आय जन हित के कार्यों पर खर्च की जाएगी। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कच्ची हल्दी के लिए 150 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की के लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया



हिन्द जनपथ

शिमला (ब्यूरो)। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 18-19 नवंबर, 2026 को सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहुंच, कवरेज और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ठोस उपायों की पहचान करना है।

बैठक के दौरान डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन हिमाचल प्रदेश को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के क्षेत्र में अपनी अग्रणी पहलों और नवोन्मेषी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश की इन पहलों से जमीनी स्तर पर सकारात्मक एवं सार्थक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश को न केवल अपने अनुभवों, उपलब्धियों और नवाचारों को अन्य राज्यों के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ज्ञान एवं अनुभवों का यह आदान-प्रदान नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने, सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित पात्र व्यक्तियों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

शिखर सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। इनमें नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम एवं नशे की मांग में कमी लाने की रणनीतियों का पुनर्निर्धारण, सुलभ छात्रवृत्तियां एवं सशक्त विद्यार्थी, दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप तथा 'विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत' शामिल हैं। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता, समावेशिता और बाधारहित वातावरण के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एंटी चिट्टा अभियान के तहत नूरपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 48.30 लाख की संपत्ति जब्त

धर्मशाला - पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर लगातार प्रभावी प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में नूरपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पीआईटी एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में पहली बार नशा तस्करी से अर्जित जब्त संपत्ति का वास्तविक एवं कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 48.30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति से संबंधित दो मंजिला आवासीय भवन का कब्जा प्राप्त कर उसे विधिवत सील किया गया है। पीआईटी एंड एनडीपीएस के तहत जब्त संपत्ति का वास्तविक कब्जा सरकार के पक्ष में प्राप्त करने की सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश की यह पहली कार्रवाई है, जो नशा तस्करों के विरुद्ध वित्तीय एवं संपत्ति संबंधी कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एसएएफईएम (एफओपी) एक्ट 1976 एवं एनडीपीएस एक्ट, 1985, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह, निवासी वार्ड नंबर-09, डमटाल, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इन संपत्तियों में गांव छन्नी, तहसील इंदौरा में दो मंजिला आवासीय भवन जिसका निर्धारित मूल्य 45,90,557 रुपये है के साथ ही नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित 2,40,440 रुपये की नकदी भी जब्त की गई है। इस प्रकार आवासीय भवन एवं नकद धनराशि सहित कुल 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

विधायक नंद लाल का राजकीय सम्मान के साथ देओठी में अंतिम संस्कार

मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

हिन्द जनपथ

शिमलाः सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे नंद लाल का बुधवार को शिमला ज़िला के रामपुर में उनके पैतृक गांव देओठी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

नंद लाल के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित सिपाही थे, जिन्होंने रामपुर क्षेत्र के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वर्गीय नंद लाल बेहद सरल, विनम्र और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि नंद लाल प्रदेश विधानसभा में हमेशा गरिमा, मर्यादा और तार्किक ढंग से अपनी बात रखते थे, जो जनहित के मुद्दों और संसदीय परंपराओं के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंद लाल के निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और समर्पित जनसेवक को खोया है। उनके जाने से सार्वजनिक जीवन में जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने परमपिता परमात्मा से दिवंगत की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक कुलदीप सिंह राठौर व हरीश जनारथा, हिमकॉन के अध्यक्ष विकेश चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।



खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान से युवाओं को नशे से दूर रखने का होगा प्रयास: यादविंदर गोमा

धर्मशालाः हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने, खेल प्रतिभाओं को निखारने तथा चिट्टा एवं अन्य नशों के विरुद्ध जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले "खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान-2026" की तैयारियों को लेकर आज एचओसीए स्टेडियम धर्मशाला में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने की।

बैठक में अभियान के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।



आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा कानून मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने तथा उनकी प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों एवं सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। यादविंदर गोमा ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, स्वस्थ समाज और नशामुक्त हिमाचल के निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक सहयोग का आह्वान किया।

यादविंदर गोमा ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह का व्यापक खेल आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अब छह खेलों को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जा रहा है तथा अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जा रही हैं। खेल गतिविधियों के माध्यम से चिट्टा एवं अन्य नशों के विरुद्ध जागरूकता का संदेश भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

स्कोडा ऑटो इंडिया ने 350 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्रों का आंकड़ा पार किया

हिन्द जनपथ

शिमलाः स्कोडा ऑटो इंडिया ने देशभर में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 193 शहरों में 350 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं जिससे ग्राहकों के लिए इसके उत्पादों और वाहन स्वामित्व संबंधी सेवाओं तक पहुँच और आसान हुई है।30 अक्टूबर 2026 को इम्फाल में अपने 350वें ग्राहक संपर्क केंद्र का उद्घाटन करके ब्रांड ने यह उपलब्धि हासिल की और इसके साथ ही मणिपुर में भी प्रवेश किया। यह विस्तार स्थापित बाजारों के साथ साथ उभरते क्षेत्रों में भी बिक्री और बिक्री पश्चात सेवाओं को ग्राहकों के और करीब पहुँचाने की स्कोडा ऑटो इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा 193 शहरों में 350 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्रों का आंकड़ा पार करना पूरे भारत में ग्राहकों के लिए स्कोडा को और करीब लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

Sr. No.	Name of works	Estimated cost	Earnest Money	Cost of Form	Time
1	R/R Damages on on Sanaba to Tippri road km 0/00 to 0/600 (SH:-C/O R/Wall at RD 0/120 to 0/160).	1043756	20875	500	2 Month
2	R/R Damages on Chamaru Jachali Madhaik road up to Garnu km 0/00 to 4/180 (SH:- C/O B/wall at Rd 1/810 to 1/955,2/000 to 2/015,3/082 to 3/089,3/201 to 3/209, & 1/840 to 1/855,and R/wall at Rd 0/550 to 0/559,2/250 to 2/263,3/118 to 3/130 ,3/175 to 3/201,4/200 to 4/209 & 4/300 to 4/303)	1280600	25000	500	2 Month

1. The **Executive Engineer,HPPWD Jubbal,Distt. Shimla**, H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on percentage rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System of the under mentioned work from the eligible and approved contractors / firms registered with HPPWD Department.
Tender document and other instruction scan be downloaded or viewed online from the portal **https://hptenders.gov.in** by the firm / individual registered on the website which is free of cost.

Key Dates:-

1.	Date of Online Publication	04-11-2026 11:00 HRS
2.	Document Download Start and End Date	04.11.2026 11:30 HRS upto 11.11.2026 11:00 HRS
3.	Bid Submission Start and End Date	04.11.2026 11:30 HRS upto 11.11.2026 11:00 HRS
4.	Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document	Online Mode
5.	Date of Technical Bid Opening	11.11.2026 11:15 HRS
6.	Evaluation of Technical Bid flowed by Opening of Financial Bid.	Date to be announced

Executive Engineer,
(B&R) Division HPPWD, Jubbal.
On behalf of Governor of Himachal Pradesh
R.No.4551/2026-2027

RNI NO. HARHIN/2002/08034, Postal Regd. No. HR/AB/54/23-25, हिन्द जनपथ के लिए स्वामी, सम्पादक एवं प्रकाशक एकान्ति रॉय गर्ग द्वारा बूथ नंबर 437-पी, सेक्टर-8, पंचकूला से प्रकाशित एवं इम्प्रैशन प्रिंटिंग एण्ड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लाट नं. 22, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला से मुद्रित। सभी विवादों का न्यायाधिकार क्षेत्र पंचकूला होगा। Mob. 9915606900 email: hindjanpath@gmail.com, argarg1610@gmail.com



सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

न्यूज डायरी

बरवाला में मिठाई की दुकानों पर मापतौल विभाग का विशेष जांच अभियान

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। मापतौल विभाग के इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने उप नियंत्रक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आज बरवाला में मिठाई की दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान बीकानेर स्वीट्स, माडू राम स्वीट्स, वीटा मिल्क बार, शर्मा स्वीट्स और सैनी मिष्ठान भंडार सहित विभिन्न दुकानों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच की गई। साथ ही, दुकानों से मिठाई खरीदकर ले जा रहे ग्राहकों को दी जा रही मिठाई के वजन का भी गहनता से निरीक्षण किया गया।



अभियान के दौरान इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मिठाई खरीदने आए ग्राहकों को भी जागरूक किया। उन्होंने ग्राहकों को बताया कि मिठाई खरीदते समय दुकानदार से डिब्बे का वजन अलग करवाएं और मिठाई का भुगतान उसके वास्तविक वजन के अनुसार ही करें। उन्होंने दुकानदारों को भी निर्देश दिए कि मिठाई तौलते समय डिब्बे का वजन शामिल न करें और ग्राहकों को निर्धारित वजन के अनुसार ही मिठाई उपलब्ध करवाएं।

इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मिठाई की तुलाई के लिए केवल विभाग द्वारा सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक कांटों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि कोई दुकानदार बिना सत्यापन वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटों का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मापतौल विभाग के सहायक अश्वनी कुमार भी मौजूद रहे।

इग्नू ने दिसंबर 2026 की सत्रांत परीक्षा के लिए ऑनलाइन असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, शोध-प्रबंध, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकम आदि जमा करने की प्रक्रिया शुरू की

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर 2026 की सत्रांत परीक्षा के लिए असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, शोध-प्रबंध, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकम आदि ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इग्नू के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित सभी पात्र विद्यार्थी इनको इग्नू समर्थ पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट, शोध-प्रबंध, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकम आदि जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2026 है, जबकि असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित इग्नू समर्थ पोर्टल लॉगिन अकाउंट के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क जमा करें। शुल्क जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए पात्र हैं तथा सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इनमें वैध पंजीकरण तथा जहां लागू हो, अध्ययन की न्यूनतम अवधि पूरी करना भी शामिल है।

उन्होंने आगे बताया कि जिन विद्यार्थियों ने अपने असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, शोध-प्रबंध, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क, प्रैक्टिकम आदि निर्धारित नियमों के अनुसार पहले ही संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों अथवा इग्नू मुख्यालय, नई दिल्ली के विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग में ऑफलाइन जमा करवा दिए हैं, उन्हें समर्थ पोर्टल के माध्यम से उनकी सॉफ्ट कॉपी दोबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

भाजपा सरकार के संरक्षण में सरेआम अवैध खनन कर रहा खनन माफिया: चौधरी अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़, 3 नवंबर। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में अवैध खनन और खनन माफिया की गतिविधियों को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर के उनेहड़ी घाट पर थाने के नजदीक खुलेआम अवैध खनन होना और दिन-रात ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में अवैध खनन सामग्री भरकर सरेआम लेके जाना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को अवैध खनन सामग्री से भरे संदिग्ध डंपर को रोकने पर एसडीएम को कथित तौर पर कुचलने की कोशिश की गई। शिकायत के अनुसार डंपर चालक ने वाहन उनकी ओर बढ़ाया और पीछे चल रही क्रेटा कार ने उनका रास्ता बाधित किया, जिससे डंपर चालक भागने में सफल रहा। यह घटना दर्शाती है कि अवैध खनन रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा भी खतरे में है। अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में खनन माफिया बेखौफ होकर प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। जब थाने के इतने नजदीक अवैध खनन हो सकता है तो प्रदेश के दूरदराज इलाकों में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण और नदियों को क्षति पहुंच रही है तथा आम जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि उनेहड़ी घाट सहित पूरे क्षेत्र में अवैध खनन की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच करवाई जाए, दोषियों, उनके सहयोगियों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एसडीएम पर हुए कथित हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को जब्त किया जाए।

पार्क हॉस्पिटल पंचकूला को मिला एनएबीएच का एक्रिडिटेशन



पंचकूलाः पार्क हॉस्पिटल पंचकूला को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) के छठे संस्करण के मानकों के तहत एक्रिडिटेशन प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति अस्पताल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह एक्रिडिटेशन क्लिनिकल केयर, मरीजों की सुरक्षा, संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा मानकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कड़े मानकों के पालन के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। साथ ही, यह चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्टता के उच्च मानकों को बनाए रखने और मरीजों को बेहतर उपचार अनुभव प्रदान करने की दिशा में अस्पताल के निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित करता है।

पार्क हॉस्पिटल पंचकूला कई सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और बीमा नेटवर्क के तहत भी सूचीबद्ध है। इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन शामिल हैं। जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के अंतर्गत नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जैसी बीमा कंपनियां शामिल हैं।

पांच साल की सुनवाई न करने वाले पार्षद सुर्खियों में, टिकट की होड़ तेज; पूर्व पार्षदों के परिवारों (ब्लडलाइन) पर भी नजर

जगदीप, हिन्द जनपथ



चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव करीब आने के साथ ही वार्डवासियों की शिकायतें और पार्षदों का प्रदर्शन अब सुर्खियों में आ गया है। पिछले करीब पांच साल से कई वार्डों में विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार, सड़कों की मरम्मत में देरी और प्रशासनिक तंत्र में फिसड्डी साबित हुए पार्षदों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मतदाता अब अपनी उपलब्धियों का हिसाब मांग रहे हैं, जबकि पार्टियां सर्वे के आधार पर टिकट तय करने में जुटी हैं। नगर निगम सदन की हालिया बैठकों में कांग्रेस और आप के पार्षदों ने सड़कों की मरम्मत और वार्ड स्तर के विकास कार्यों में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ पार्षदों ने पोस्टर लेकर मेयर के सामने धरना दिया और नारे लगाए कि उनकी सड़कें कब बनेंगी। मेयर ने आश्वासन दिया कि काम जल्द शुरू होंगे, लेकिन विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि ठेकेदारों की कार्यप्रणाली और अधिकारियों द्वारा कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर सदन की मंजूरी से बचने की कोशिश से काम अटके रहे। एक पार्षद ने अधिकारियों द्वारा करीब 62 करोड़ रुपये के कार्यों का हिसाब भी मांगा। वार्डवासी लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि कई पार्षद पांच साल तक उनकी सुनवाई नहीं करते रहे। प्रशासनिक तंत्र के जरिए विकास कार्यों में फिसड्डी साबित होने वाले पार्षद अब चुनावी मौसम में सक्रिय दिख रहे हैं। कुछ पार्षद अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को न्यूज कटिंग भेजकर आगामी चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं। वे अपनी उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से उजागर करने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि मतदाता कह रहे हैं कि वे इन पांच साल की असलियत को अच्छी तरह याद रखे हुए हैं। मीडिया हाउस भी इन मुद्दों को कवरेज दे रहे हैं, जिससे पार्षदों की उपलब्धियां और कमियां दोनों चर्चा में हैं।पार्टियों ने भी सर्वे करवाकर टिकट तय करने का रास्ता अपनाया है। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी स्वतंत्र सर्वे एजेंसियों के जरिए उम्मीदवारों की जमीनी पकड़, लोकप्रियता और जीत की संभावना का आकलन कर रही हैं। कई वार्डों में एक से ज्यादा दावेदार हैं, इसलिए पार्टियां स्थानीय सिफारिशों के बजाय सर्वे रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प आयाम जुड़ गया है। पूर्व पार्षदों के परिवारों को लंबे समय से भूल चुकी पार्टियां इस बार उन पर भी दांव खेल सकती हैं। करीब दस साल पुराने पार्षदों का मतदाताओं में आज भी बोलबाला है। कई वार्डों में लोग उनकी ब्लडलाइन को अभी भी अपना नेता देखना चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी के पार्षदों की लोकप्रियता और स्थानीय जुड़ाव को देखते हुए पार्टियां उनके बेटे-बेटियों या करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं। सर्वे रिपोर्ट में अगर इन परिवारों की पकड़ मजबूत निकलती है तो मौजूदा पार्षदों की जगह नई-पुरानी ब्लडलाइन को तरजीह मिलने की संभावना बढ़ गई है। चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है। इस बीच नगर निगम ने कई विकास कार्यों के प्रस्ताव मंजूर किए हैं, जिनमें सड़कें, पार्क, पानी की सप्लाई और स्वच्छता संबंधी काम शामिल हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार अभी भी सुस्त है और कई पुरानी शिकायतें लंबित हैं। मतदाता अब इन पांच साल के रिकॉर्ड को तौलकर अपना फैसला करेंगे।

निदेशक डॉ. ललित जैन ने की जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा, समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। निदेशक जनगणना परिचालन एवं नागरिक पंजीकरण, हरियाणा डॉ. ललित जैन ने आज लघु सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में उपायुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी, पंचकूला, श्री सतपाल शर्मा तथा नगराधीश एवं उप-प्रधान जनगणना अधिकारी सुश्री जागृति भी उपस्थित रहीं।



डॉ. ललित जैन ने बताया कि जनगणना का दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी, जनवरी 2027 में शुरू होने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस चरण के सफल एवं समयबद्ध संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। विशेष रूप से पर्याप्त संख्या में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या गणना जनगणना का एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक चरण है, जिसमें काफी समय लगता है और इसके लिए अतिरिक्त मानव संसाधन के साथ-साथ बेहतर योजना एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। इस दौरान नागरिकों से लगभग 40 विभिन्न प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि जनसंख्या से संबंधित आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जा सकें।

डॉ. जैन ने जनगणना के प्रथम चरण- मकान सूचीकरण का कार्य सफलतापूर्वक एवं निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपायुक्त एवं प्रधान जनगणना अधिकारी श्री सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन जनगणना के दूसरे चरण को भी निर्धारित समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा करेगा।

दिवाली पर प्रदेश के अस्पताल अलर्ट मोड पर

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जारी की विशेष एडवाइजरी

जगदीश, हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिवाली पर्व के दौरान अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए विशेष सलाह जारी की है। त्योहार के समय पटाखों और अन्य हादसों के कारण जलने और सांस संबंधी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बर्न-वार्ड अलग से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।



आपातकालीन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और बर्न ट्रीटमेंट किट जैसी आवश्यक दवाओं व चिकित्सा आपूर्ति का पहले से ही प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आतिशबाजी या किसी भी प्रकार दुर्घटना के शिकार लोगों का त्वरित इलाज संभव हो सके, इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में 20 से अधिक बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली के दिन सामान्य दिनों की तुलना में सड़क हादसों, झुलसने और आंखों की चोटों की घटनाओं में इजाफा होता है, जिसे देखते हुए इमरजेंसी विभाग के अलावा नेत्र रोग (ऑप्थैल्मोलॉजी), आर्थोपेडिक और सर्जरी विभागों में भी बेड सुरक्षित रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि नेत्र रोग, आर्थोपेडिक और सर्जरी विशेषज्ञों को अलर्ट मोड और ऑन-कॉल ड्यूटी पर रखा जाए ताकि पीड़ितों को तुरंत और प्रभावी इलाज मिल सके।

दिवाली के दिन किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तैनात रहने का आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त बर्न मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, बेड, आई/वी स्टैंड, आई/वी सोलूशन्स और एंटीबायोटिक्स की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अस्पतालों में इलाज के दौरान मां और नवजात शिशु को साथ रखने की दिशा में हरियाणा की पहल, फैमिली सेंटर्ड केयर का होगा विस्तार

जगदीश, हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की जान बचाने की तैयारियों को और मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से 19 अतिरिक्त नवजात वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने जा रही है। प्रदेश की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) में पहले से 54 नवजात वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इन 19 नए वेंटिलेटर के जुड़ने से गंभीर परिस्थितियों में नवजात शिशुओं को समय पर श्वसन सहायता उपलब्ध करवाने की क्षमता और मजबूत होगी।



इसके साथ ही हरियाणा सरकार विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों को एकीकृत मातृ-नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (एमएनसीयू) के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेशव्यापी पहल कर रही है। इसके तहत चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में अस्पताल में उपचार के दौरान मां को अपने नवजात शिशु के साथ रहने की सुविधा दी जाएगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस पहल का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती नवजात शिशुओं को उनकी माताओं से अनावश्यक रूप से अलग होने से बचाना है। इसके लिए विशेष चिकित्सा उपचार के साथ मां की निरंतर उपस्थिति, स्तनपान में सहयोग और शिशु की देखभाल में परिवार की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत माताओं को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अपने शिशुओं के पास रहने और प्रशिक्षित डॉक्टरों तथा नर्सों की देखरेख में उनकी देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 'जीरो सेपरेशन' यानी मां और नवजात को अलग न रखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के तहत चिकित्सकीय रूप से संभव होने पर विशेष नवजात शिशु देखभाल की आवश्यकता वाले मामलों में भी मां और शिशु को साथ रखने पर जोर दिया जाता है।

यह मॉडल विशेष रूप से समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रखने, दूध पिलाने में सहायता, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने और निरंतर चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

बड़ा कदम: एसटीपी के आसपास दुर्गंध दूर करने के लिए 24 प्लांटों पर लगेंगे एक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम, 3,865.806 लाख रुपये होंगे खर्च : मंत्री रणबीर गंगवा

चंडीगढ़- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के आसपास फैलने वाली दुर्गंध से अब लोगों और किसानों को राहत दिलाने की तैयारी है। हरियाणा में ट्रीटेड वेस्ट वाटर की दुर्गंध कम करने के लिए 24 एसटीपी पर एक्टिवेटेड कार्बन आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे। इस पर करीब 3,865.806 लाख रुपये रुपये खर्च होने का अनुमान है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसटीपी के आसपास दुर्गंध की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ट्रीटेड पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करें।

मंत्री रणबीर गंगवा हरियाणा सिविल सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 25 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की सर्कलवार समीक्षा की गई। विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती रेणु सोगन, इंजीनियर-इन-चीफ श्री देवेंद्र दहिया सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, जबकि प्रदेशभर के अधीक्षक अभियंता (एसई), कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) और उपमंडल अभियंता (एसडीओ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

भाजपा टिकट की होड़ संजय टंडन, अरुण सूद और जितेंद्र मल्होत्रा के इर्द-गिर्द घूम रही

चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव करीब आने के साथ भाजपा में टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। शहर इकाई में तीन वरिष्ठ नेताओं—संजय टंडन, अरुण सूद और जितेंद्र पाल मल्होत्रा—के इर्द-गिर्द सियासी समीकरण बनते-बिगड़ते दिख रहे हैं। प्रत्येक नेता के अपने समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक से बढ़कर एक वर्चस्व है, जिससे टिकट की लड़ाई और भी दिलचस्प बन गई है।संजय टंडन लंबे समय तक चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने करीब एक दशक तक इकाई की कमान संभाली। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार बने और नजदीकी मुकाबले में हारे। हाल ही में वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और चंडीगढ़ के मुद्दों, खासकर संपत्ति हस्तांतरण की समस्याओं को उठाया। टंडन के समर्थक उन्हें अनुभवी और संगठन से जुड़े नेता मानते हैं। उनके खेमे में कई पुराने कार्यकर्ता और कुछ मौजूदा पार्षद सक्रिय हैं, जो टिकट बंटवारे में उनके प्रभाव को मजबूत मानते हैं।अरुण सूद पूर्व मेयर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वे टंडन के बाद अध्यक्ष बने थे। सूद के समर्थक उन्हें स्थानीय मुद्दों और वार्ड स्तर की राजनीति में मजबूत मानते हैं। उनके खेमे में भी कई नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जो टिकट प्रक्रिया में अपनी आवाज रखने की कोशिश कर रहे हैं।



जितेंद्र पाल मल्होत्रा वर्तमान में चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे पिछले कुछ वर्षों से इकाई की कमान संभाल रहे हैं और हालिया संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उनके समर्थक नेताओं में भी अच्छा वर्चस्व दिखता है। कई मौजूदा पार्षद और संगठन से जुड़े लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, तीनों नेताओं के अपने-अपने समर्थक समूह हैं। हर खेमे में दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। वार्ड आरक्षण तय होने और सर्वे शुरू होने के बाद टिकट की होड़ और तेज हो गई है। कई वार्डों में एक से ज्यादा दावेदार हैं। पार्टी उच्च कमान सर्वे रिपोर्ट, जीत की संभावना और संगठनात्मक ताकत को ध्यान में रखकर फैसला करेगी।इस बीच पार्टी में एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। हालिया कोर कमेटी बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व ने बूथ स्तर की मजबूती और समन्वय पर बल दिया। तीनों नेताओं के खेमे सक्रिय हैं, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली हाईकमान का होगा। टिकट सूची आने तक हर खेमा अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है।चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है।

पंचकूला में आयोजित 'वोट बचाओ–देश बचाओ' चौपाल के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान

पंचकूला – पंचकूला में आयोजित 'वोट बचाओ–देश बचाओ' चौपाल कार्यक्रम के दौरान संयुक्त प्रेस वार्ता में 'वोट बचाओ देश बचाओ' अभियान के जिला प्रभारी शमशेर गोगी , पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन, कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान,एवं हरियाणा महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सुधा भारद्वाज ने लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और जनता के मताधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल राजनीतिक दलों की नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।



वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सुधा भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। वोट केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की आवाज और लोकतांत्रिक अधिकार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस उद्देश्य को लेकर जनता के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर लोगों को उनके वोट के महत्व के प्रति जागरूक करें। जिला प्रभारी शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशानुसार 4 से 25 नवंबर तक प्रदेशभर में 'वोट बचाओ–देश बचाओ' जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर आमजन से सीधा संवाद करेंगे और चुनावी पारदर्शिता, मताधिकार की सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेंगे।

रबी सीजन में किसानों को न हो पानी की कमी: श्रुति चौधरी

चंडीगढ़- हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चालू रबी सीजन के दौरान प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया जाए ताकि फसलों की बिजाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी की सीमित उपलब्धता के बावजूद राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर क्षेत्र के किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिले। इसके लिए वितरण प्रणाली की समीक्षा के साथ-साथ नहरी पानी की निरंतर निगरानी भी की जा रही है।

वे आज यहां के पानी की आपूर्ति को लेकर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक मे बाढ़ नियंतत्रण उपायों के साथ-साथ वन विभाग से संबंधित स्वीकृतियों, भूमि की निशानदेही तथा पंपों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल भी बैठक में मौजूद रहे। श्रीमती श्रुति चौधरी ने निर्देश दिए कि पानी के आवंटन से संबंधित पुराने रिकॉर्ड, निर्धारित मानदंडों का आकलन किया जाए और समय-समय पर पानी की उपलब्धता, सिंचित क्षेत्र और किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा की नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए लोगों को जागरुक किया जाए और इस मुहिम में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

अपराध नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर डेटा आधारित रणनीति अपनाएं अधिकारी: डीजीपी अजय सिंघल

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने आज पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में अपराध नियंत्रण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपराध के आंकड़ों का विश्लेषण, थाना स्तर पर अपराध की प्रवृत्तियों की पहचान, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने की तैयारियों तथा अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

डीजीपी श्री अजय सिंघल ने कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के धरना-प्रदर्शनों से कई बार कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और



निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस बल हर स्तर पर आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों से लैस (Well Equipped) रहे। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को जिलेवार धरना-प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण कर उनके कारणों की पहचान करने तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।

डीजीपी श्री अजय सिंघल ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए सटीक और बेहतर डेटा का होना बेहद जरूरी है। यदि हमारे पास अपराध से संबंधित विस्तृत और विश्वसनीय आंकड़े होंगे तो हम बेहतर रणनीति तैयार कर सकेंगे, जिससे अपराध की रोकथाम में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा एसओपी तैयार की गई है। सभी अधिकारी इसका गंभीरता से पालन करें और निर्धारित एसओपी के अनुरूप ही कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और उन्हें अपने एक्शन प्लान की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

बैठक के दौरान थाना स्तर पर अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था श्री राकेश आर्य ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध के बदलते पैटर्न और वृद्धि वाले क्षेत्रों की जानकारी दी। डीजीपी ने निर्देश दिए कि हत्या, डकैती सहित अन्य अपराधों में वृद्धि के कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के पहले दस महीनों में प्रदेश में कुल अपराध में 9.41 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, लेकिन थाना स्तर पर अपराध की लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को अपराध की प्रकृति और स्थान के अनुसार पेट्रोलिंग बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा अन्य निवारक उपाय अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही, अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने की बात कही।

संक्षिप्त समाचार

अपने ही कस्टमर से मुकाबला करना अच्छी रणनीति नहीं, अडानी ग्रुप का एयरलाइंस सेक्टर में उतरने से इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई, लखनऊ और अहमदाबाद समेत देश के 9 एयरपोर्ट चला रहा अडानी ग्रुप फिलहाल एयरलाइंस सेक्टर में प्रवेश नहीं करेगा। ग्रुप का ध्यान अपने एयरपोर्ट कारोबार के विस्तार पर है। आने वाले समय में देश के 11 और एयरपोर्ट के निजीकरण की प्रक्रिया में भी वह हिस्सा लेगा। यह जानकारी मंगलवार को एयरोसिटी में चल रहे एविएशन इंडिया एंड साउथ एशिया 2026 कॉन्फ्रेंस में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के ष्टश्वह्म अरुण बंसल ने दी। एयरलाइन कारोबार में उतरने की चर्चाओं पर



विराम लगाते हुए बंसल ने कहा कि एयरलाइंस की ग्राहक हैं और अपने ग्राहकों से प्रतिस्पर्धा करना अच्छी रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि ।रुऔर अडानी ग्रुप को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। हाल में आई थी कि अडानी ग्रुप एयरलाइन बिजनेस में उतर सकता है और इसके लिए उसने सरकार से नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया था। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया था कि एयरलाइन बिजनेस में उतरने पर विचार करने वाली खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं। अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। माना जा रहा था कि सरकार एयर इंडिया और इंडिगो के दबदबे को खत्म करने के लिए यह नियम बदलने पर विचार कर रही है। अभी इन दोनों कंपनियों की डोमेस्टिक मार्केट में करीब 90 फीसदी हिस्सेदारी है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों ने इसका विरोध किया है। उनका तर्क है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एयरलाइन का मालिक बनने की अनुमति देने से हितों का भारी टकराव पैदा होगा। साथ ही इससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। सरकार वाराणसी, अमृतसर और रायपुर समेत 11 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है।

अनिल अंबानी ग्रुप पर कसता शिकंजा, अब तक 23,100 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, एजेंसी। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 2 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, जमीन के टुकड़ों और पवन चक्कियों समेत 510 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। एजेंसी का आरोप है कि ग्रुप ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जरिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। उसे व्यक्तिगत लाभ और टैक्स हैवन देशों में डायवर्ट किया है। मंगलवार को अनिल अंबानी समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 510 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में की गई है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। 247.12 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई। इनमें डसॉल्ट फाल्कन 2000 और एम्ब्रेयर के दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में 6 जमीन के प्लॉट और एक ऑफिस परिसर शामिल हैं। वहीं, मामले में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें तमिलनाडु की दो पवन चक्कियां, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश शामिल हैं।
जांच एजेंसी का दावा है कि अनिल अंबानी समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक धन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की। कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत इस्तेमाल किया। इन पैसों को भारत से बाहर टैक्स हैवन देशों में भेजा।

साबुत चावल तो छोड़िए, टूटे चावल भी लगा रहा है छलांग, निर्यात पर लगेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, एजेंसी। महंगे होते चावल के दाम ने सरकार की नींद उड़ा दी है। शायद यही वजह है कि अब फूड कार्पोरेशन या के सरप्लस चावल से बनने वाले इथेनॉल की ऊपरी सीमा तय यानी कर दी गई है। इससे पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब खबर आई है कि खुले बाजार में शत प्रतिशत टूटे हुए चावल या कीमतों में भी तेज उछाल हो रहा है। इसे देखते हुए हो सकता है कि सरकार इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे। वैसे भी इस साल अभी तक धान का उत्पादन घटने की ही खबर आई है।

पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के लिए हर साल सरकार की तरफ से टेंडर निकाला जाता है। इसी टेंडर में इथेनॉल निर्माण और सप्लाई से जुड़ी नियम एवं शर्तों की जानकारी होती है। सरकार की तरफ से 3 नवंबर 2026 को जारी रिवाइज्ड टेंडर कंडीशंस में बताया गया है कि इस साल के शुरुआती तीन तिमाहियों में एफसीआई के सरप्लस चावल से 3.24 अरब लीटर से अधिक इथेनॉल नहीं बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत में गन्ने के रस के अलावा



चावल और मक्का का इथेनॉल बनाने में उपयोग होता है। चावल में भी अधिकतर टूटे चावल का ही उपयोग इसे बनाने में होता है। कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान देना होगा चावल निर्यातकों के संगठन इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के महानिदेशक विनोद कौल का कहना है कि चावल की कीमतों में इस बढ़ोतरी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रोकन राइस की कीमत बढ़ कर 360 डॉलर प्रति टन के ऊपर चला गया है। ऐसे में निर्यात करना पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है। लेकिन सरकार भी चाहेगी कि इस तरह के चावल की घरेलू उपलब्धता बनी रहे। इसलिए हो सकता है कि इस इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे।

चावल की कीमत में बढ़ोतरी

बीते कुछ महीनों के दौरान ही चावल की कीमतों में खासी बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह विदेशी बाजारों में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी, देश में धान की बुवाई के रकबे में कमी और कुछ और कारण बताए जा रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो 2 नवंबर 2026 को चावल की अखिल भारतीय औसत थोक कीमत 4380.49 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई थी। मतलब कि करीब 44 रुपये प्रति किलो। यह एक साल पहले इसी तारीख को 3747.44 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी एक साल में ही चावल के दाम करीब 17 फीसदी बढ़ गए। यह तो हुई थोक बाजार की बात। जब आप खुदरा बाजार में चावल खरीदने जाते हैं तो वहां तो स्थिति अलग ही है।

टूटे चावल का दाम भी बढ़े

उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक बीते एक पखवाड़े में टूटे चावलों की कीमतों में भी 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने 10 अक्टूबर को ब्रोकन राइस की ऑल इंडिया एवरेज प्राइस 2883 रुपये प्रति क्विंटल थी। यह दो नवंबर 2026 को बढ़ कर 3036 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में कम से कम टूटे चावलों का निर्यात तो रोक ही सकती है। चावल की कीमतों में इस बढ़ोतरी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रोकन राइस की कीमत बढ़ कर 360 डॉलर प्रति टन के ऊपर चली गई है। केंद्र सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल खरीफ मौसम के दौरान धान की फसल की बुवाई में 3.46 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एक साल पहले इस दौरान 449.18 लाख एकड़ में धान की फसल बोई गई थी। इस साल यह क्षेत्र घट कर 433.62 लाख एकड़ रह गया है। खरीफ फसल में धान की बुवाई का रकबा घटने की मुख्य वजह मानसूनी बारिश की कमी से जोड़ा जा रहा है।

60 महीने पहले शुरुआत, अब हर साल 6 करोड़, नौकरी छोड़ने के बाद ऐसे खड़ा किया बिजनेस

यह ब्रांड बांस और कॉटन-लाइक्रा के ब्लेंड वाले टी-शर्ट और इनरवेयर बनाता है



नई दिल्ली, एजेंसी। यह कहानी है सुप्रीत कश्यप की। वह मैसूर के रहने वाले हैं। 2017 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वह एक्सेंचर में नौकरी करने लगे थे। फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर अक्टूबर 2021 में अपने स्टार्टअप की नींव रखी। इसका नाम 'वेलबी' है। यह ब्रांड बांस और कॉटन-लाइक्रा के ब्लेंड वाले टी-शर्ट और इनरवेयर बनाता है। आज इसका सालाना टर्नओवर 6 करोड़ रुपये पहुंच गया है। आइए, यहां सुप्रीत कश्यप की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। ब्रांड को छोड़कर सुप्रीत के ब्रांड को चुनने से इसके क्व2क्कारोबार में दोगुना उछाल आया। हर महीने ब्रांड 20,000 से अधिक उत्पाद बेचता है। यह स्टार्टअप साबित करता है कि सही प्रोडक्ट क्वालिटी और धैर्य के साथ स्थापित दिग्गजों को भी कड़ी टक्कर दी जा सकती है।

नौकरी छोड़कर की शुरुआत

सुप्रीत कश्यप मैसूर के एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं। उनके परिवार में पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया था। सुप्रीत ने 2017 में इंजीनियरिंग पूरी की। फिर एक्सेंचर में 6 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी करने लगे। हालांकि, उनका मन नौकरी में नहीं लगा। एक साल में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर दिल्ली से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया। अक्टूबर 2021 की बात है। उन्होंने 10 लाख की सेविंग और माता-पिता की मदद से 'इको एम्ब्रेस डिजाइनर क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड' के तहत 'वेलबी' ब्रांड की शुरुआत की। शुरुआत में हाथ से बने प्रोडक्ट बेचने में असफलता मिली। इसके बाद उन्होंने बांस के रेशों से बने कपड़ों का रुख किया। 999 रुपये की एक राउंड-नेक टी-शर्ट से अपने ब्रांड की औपचारिक शुरुआत की।

सामने आईं कई चुनौतियां

यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कंपनी का पहले साल का रेवेन्यू सिर्फ 11.5 लाख रुपये रहा। 2024 की पहली छमाही में कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपये का घाटा हो रहा था। स्टार्ट-अप के लिए मल्टी-टास्किंग कर्मचारी तलाशना और फैब्रिक की क्वालिटी तय करना बड़ी चुनौतियां थीं। हालांकि, उत्पादों की बेहतरीन क्वालिटी, पसीना सोखने की क्षमता और कम्फर्ट के चलते पुराने ग्राहकों के दोबारा खरीदारी करने से सुप्रीत का हौसला बढ़ा। 2023 में 75 लाख रुपये और 2024 में 2.5 करोड़ रुपये की बिक्री करके पिछले वित्तीय वर्ष में ब्रांड का टर्नओवर 6 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इसमें करीब 60 कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। ब्रांड के बांस के कपड़े तिरुपुर (तमिलनाडु) में बनते हैं। बेंगलुरु के नेलमंगला में इसका 5,500 वर्ग फीट का मुख्य वेयरहाउस है। इसका फोकस तेजी से बदलते फैशन के बजाय आराम पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्राहकों की तारीफ के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राहकों ने खुद कंपनी में 3 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट फंड लगाया। अभी इसकी 97 फीसदी बिक्री अपनी वेबसाइट के अलावा अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है। बाकी 3 फीसदी मैसूर और मुंबई स्थित दो ऑफलाइन स्टोर्स से आती है। सीधे ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचने के अलावा ब्रांड ने कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। जेरोधा, मेटा, जेडब्ल्यू मैरियट, सिस्को, अमेजन और एडोब जैसी टॉप कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए इसकी बैम्बू-ब्लेंड टी-शर्ट्स ऑर्डर करती हैं।

अमेरिका में चुनाव और जापान में हाहाकार! तीन महीने के लो पर पहुंचा शेयर बाजार



नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के आज हो रहे मिडटर्म चुनावों पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। निवेशकों को यह जानने की उत्सुकता है कि इसके बाद वैश्विक राजनीति में स्थितरता आएगी या नहीं। यह खासकर इक्विटीज के लिए बेहद अहम है। इन चुनावों से तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले दो साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में कौन सी पार्टी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट को कंट्रोल करेगी। बाजार में तेजी आई है लेकिन जापान में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से एआई से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट आई है और निक्केई तीन महीने के लो पर चला गया। माना जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की जीत से डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को लेकर नियम सख्त हो सकते हैं। साथ ही एआई इन्फ्रा पर कंपनियों के खर्च में गिरावट आ सकती है। निक्केई शेयर एवरेज 3.56 फीसदी गिरावट के साथ 60,835.36 अंक पर आ गया जो 29 जुलाई के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। ब्रॉडर टॉपिक्स भी 2.45 फीसदी गिरावट के साथ 3832.27 अंक रह गया। निवेशकों को आशंका है कि डेमोक्रेटिक का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। इससे एआई इन्फ्रा पर सख्ती हो सकती है जिसका व्यापक असर टेक, हेल्थकेयर, बैंकिंग और क्रिप्टोकरेंसीज जैसे सेक्टर पर पड़ सकता है।

इस दिवाली घर ही नहीं, अपने पोर्टफोलियो को भी चमकाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक के निवेशक और ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो का काफी ध्यान देते हैं। वे समय के साथ-साथ इसको देखते हैं और इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव भी करते हैं। इसके लिए वे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को तगड़ी रणनीति के साथ करते हैं। वहीं, इस दौरान देश के लोगों में दिवाली का उमंग देख जा रहा है। लोग इस खास त्योहार को लेकर अपने घरों को चमकाने में लगे हुए हैं। इस बीच एक्सपर्ट का कहना है कि दिवाली पर केवल घरों को ही ना चमकाएं बल्कि अपने पोर्टफोलियो को भी चमकाएं। आइए जानते हैं कि इस दिवाली आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे 'सुपर-रीसेट' कर सकते हैं। इसके लिए हम यहां एक्सपर्ट के जरिए आपको खास 5 स्टेप बताने जा रहे हैं।



कैसे करें अपने पोर्टफोलियो को रीसेट

लोग अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई निवेश के रूप में रखते हैं। मतलब कि अपने 100 फीसदी फंड को किसी एक जगह निवेश ना करके कई जगहों पर निवेश किए होते हैं। इनमें इमरजेंसी फंड, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स एसआईपी समेत अन्य निवेश शामिल होते हैं। इसके अलावा लोग लोन, इंश्योरेंस और लायबिलिटीज को लेकर भी अपने पोर्टफोलियो में हिसाब रखते हैं।

अब आइए जानते हैं कि इन निवेश और खर्च को लेकर अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीसेट किया जाता सकता है। इन्हें हम एक्सपर्ट से कुल 5 स्टेप के जरिए समझेंगे, जिसे हमारे सहयोगी ईटी वेल्थ की एक रिपोर्ट में बताया गया है।

फाउंडेशन करें चेक छह महीने की इमरजेंसी सेविंग्स बनाए रखें। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस को रिव्यू करें। लोन और लायबिलिटीज़ का हिसाब रखें।

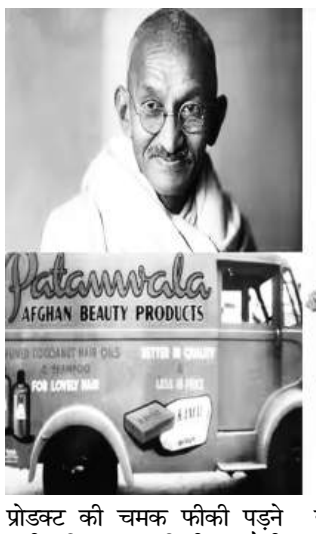
कब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स का सवाल

नईदिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अहम अपडेट है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को एक साल, 3 नवंबर 2026 को ही पूरा हो गया। करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी बता दें आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से मई 2027 के आसपास आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है। वहीं, कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने और 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी गई है। हालांकि, यह कर्मचारियों की मांग है, न कि आयोग की ओर से तय की गई सैलरी। आयोग अपनी सिफारिशों में क्या प्रस्ताव देता है और सरकार उसे कितना मंजूर करती है, यह बाद में स्पष्ट होगा।

एक नाम जिसे बचाने के लिए महात्मा गांधी आए थे सामने

भारत की पहली ब्यूटी क्रीम 'अफगान स्नो' की कहानी

नई दिल्ली, एजेंसी। अफगान स्नो। भारतीय कॉस्मेटिक इतिहास में इसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 1919 में यह लॉन्च हुई थी। भारत की यह पहली मल्टीपर्पज ब्यूटी क्रीम थी। इसके साथ राजा-महाराजाओं का नाम, महात्मा गांधी का आशीर्वाद, बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों और भारत की पहली 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता का इतिहास जुड़ा है। आधुनिक दौर की गोरेपन का दावा करने वाली क्रीमों के उलट अफगान स्नो ने कभी रंगभेद को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि, विदेशी नाम और पैकेजिंग के चलते स्वदेशी आंदोलन में घिरे इस ब्रांड को बचाने के लिए खुद महात्मा गांधी को सामने आना पड़ा था। लेकिन, बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े बजट और प्रतिस्पर्धा के आगे इसका प्रभाव समय के साथ कम होता चला गया।इसके बाद भारतीय जनता ने इसका बहिष्कार खत्म किया। साथ धीरे-धीरे





प्रोडक्ट की चमक फीकी पड़ने लगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एंट्री और 'फेयर एंड लवली' जैसे गोरेपन का दावा करने वाले भारी-भरकम विज्ञापन बजट वाले उत्पादों के आने से प्रतिस्पर्धा बहुत मुश्किल हो गई।

पाटनवाला परिवार की यह छोटी कंपनी कॉर्पोरेट्स के विशाल मार्केटिंग बजट और आधुनिक पैकेजिंग का सामना नहीं कर सकी। वैसे तो अफगान स्नो का निर्माण आज भी पाटनवाला परिवार करता है। लेकिन, यह ऐतिहासिक ब्रांड अब कॉस्मेटिक इतिहास का यादगार पन्ना बनकर ही रह गया है।

पहली 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता की स्पॉन्सरशिप

पाटनवाला ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया। इसके बजाय अपनी मजबूत व्यावसायिक दूरदर्शिता से इसे बॉम्बे के उच्च वर्ग में स्थापित भी किया। वह बड़े बॉल रूम डांस और पार्टियों का आयोजन करते थे। इनमें नरगिस, राज कपूर और देविका रानी जैसी मशहूर बॉलीवुड हस्तियां शामिल होती थीं। देविका रानी ने तो इसे 'ईश्वर का उपहार' बताकर इसका प्रमोशन किया था। यही नहीं, पाटनवाला की कंपनी ने 1952 में बॉम्बे में आयोजित भारत की पहली 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता को भी स्पॉन्सर किया था। इसमें इंद्राणी रहमान विजेता बनी थीं। सबसे खास बात यह रही कि उस दौर में भी अफगान स्नो ने त्वचा के रंग को गोरा करने का कोई दावा नहीं किया। इसके बजाय यह प्रदूषण से त्वचा को बचाने और प्राकृतिक सुंदरता निखारने पर केंद्रित रही। हालांकि, 'अफगान स्नो' की इस कामयाबी के साथ अनोखा विवाद भी जुड़ गया। वैसे तो यह प्रोडक्ट पूरी तरह स्वदेशी था। लेकिन, इसकी खुशबू स्विट्जरलैंड के फॉर्मूलेशन से तैयार होती थी। कांच की बोतलें जर्मनी से आती थीं। लेबल जापान में छपते थे। इस विदेशी नाम और पैकिंग के चलते स्वदेशी आंदोलन के चरम पर भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे विदेशी सामान समझ इसका बहिष्कार शुरू कर दिया। संकट में फंसे पाटनवाला ने महात्मा गांधी से मदद मांगी। गांधी जी ने खुद एक बयान और विज्ञापन जारी कर देशवासियों को साफ किया कि 'अफगान स्नो' पूरी तरह से देसी उत्पाद है।

कैब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय को मिलेंगे कई तरह के बेनिफिट्स

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में 1.2 करोड़ से अधिक गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। किसी कंपनी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए शॉर्ट टर्म, प्रोजेक्ट-बेस्ड या ऑन-डिमांड काम करने वाले लोगों को गिग वर्कर्स कहते हैं। डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और सर्विस प्रोवाइडर इस कैटगरी में आते हैं। सरकार ने गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया है। उनके सोशल सिक्योरिटी को फंड करने के लिए सरकार एग्रीगेटर्स के कुल टर्नओवर के बजाय हर ट्रांजैक्शन पर 2 फीसदी लेवी लगाने पर विचार कर रही है।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

क्र. सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा खुलने कि तिथि समय	अनुमानित लागत रुपये	धरोहर राशि रुपये	कार्य पूरा करने की अवधि
1.	OT-37/ 2026-27	प्रोविजन ऑफ सीसीटीवी कैमरा एट स्टेशन मास्टर रूम/ पैनल रूम्स एंड रिले रूम ओवर यूएमबी डिवीजन।	01.12.2026 at 15.00 hrs.	Rs. 5,28,89,583.17/-	Rs. 10,57,800/-	180 दिन
2.	OT-38/ 2026-27	रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलाईव्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजेस विद आईपी बेस्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजेस एट सहारनपुर, जगाधरी वर्कशॉप, घूरी, पटियाला, राजपुरा, सरहिंद, रूपनगर, नंगल डैम, चंडीगढ़, कालका, बठिंडा, शिमला एंड अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन्स ओवर यूएमबी डिवीजन।	01.12.2026 at 15.00 hrs.	Rs. 4,77,76,119.99/-	Rs. 9,55,500/-	270 दिन
3.	OT-39/ 2026-27	प्रोविजन ऑफ रेलनेट कनेक्शन्स इन सी एंड डब्ल्यू वर्कशॉप एट जगाधरी वर्कशॉप एंड कालका वर्कशॉप।	01.12.2026 at 15.00 hrs.	Rs. 3,76,59,156.97/-	Rs. 7,53,200/-	270 दिन
4.	OT-40/ 2026-27	द वर्क फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव एनुअल मैंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एएफडीएएस ओवर अंबाला डिवीजन फॉर टू इयर्स।	01.12.2026 at 15.00 hrs.	Rs. 1,11,84,128.64/-	Rs. 2,23,700/-	24 महीने

नोट:- वरि. मंडल सिग. एवं टेली. इंजी./उ.रे., डी.आर.एम. ऑफिस, रेल बिहार, अम्बाला छावनी के द्वारा इच्छुक निविदाकारों से उपरोक्त संदर्भित कार्यों हेतु खुली निविदा दशार्यी गयी तिथि अनुसार **15:00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। निविदाकारों के द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन प्रतिलिपि अपलोड करें। **1.** टैन्डर डाकूमेंटस व निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे बेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर लाग ऑन करें। **2.** निविदाकारी को ई-टेण्डरिंग में भाग लेने के लिए उनके पास क्लास-III डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा उन्हें उपरोक्त साइट पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। निविदाकारों से निवेदन है कि टैन्डर नोटिस और टेन्डर डाकूमेन्टस में दी गई हिदायतों/शर्तों इत्यादि को टैन्डर डालने से पहले भली भांति पढ़ ले।

सं.: एस. डब्लू/सिग/अंबाला/एन.आई.टी-12-2026-27 दिनांक: 04.11.2026 3860/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ



कैसे बनते हैं डॉक्टर

डॉक्टर बनना निस्संदेह सबसे अधिक मांग वाले प्रोफेशन में से एक है। डॉक्टरों की मांग न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में है। यह पेशा न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि डॉक्टरों की तरफ से समाज में दिए गए योगदान के कारण महान माना जाता है। भारत में एमबीबीएस की डिग्री अक्सर पेशे से संबंधित होती है, लेकिन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए इस कोर्स को करने के अलावा और भी बहुत कुछ जरूरी है.....

भारत में वर्तमान में क्या है डॉक्टरों की स्थिति

भारत में सरकारी और निजी दोनों संस्थान/विश्वविद्यालय हैं, जो एमबीबीएस कराते हैं। देश में इस समय एमबीबीएस की सीटों की कुल संख्या 1,07000 से कुछ अधिक है। वहीं, इन सीटों पर प्रवेश के लिए लगभग हर वर्ष 20 लाख छात्र NEET UG परीक्षा देते हैं। हालांकि, सिर्फ 5 प्रतिशत अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई किया जाता है।

क्या है एडमिशन का नियम

नीट यूजी परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित राज्य की अथॉरिटी की तरफ से आयोजित होने वाली काउंसलिंग में भाग लेना होता है। क्योंकि राज्य कोटे की सीटों पर राज्य अथॉरिटी की तरफ से एडमिशन दिया जाता है। जबकि केंद्र कोटे की सीटों पर एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग आयोजित की जाती है। एमबीबीएस भारत में 5.5 वर्ष का है, जिसमें 4.5 वर्ष का पाठ्यक्रम और एक वर्ष की इंटर्नशिप शामिल है।

एम्स जैसे संस्थानों में पीजी के लिए देना होता है ये एग्जाम

एम्स दिल्ली जैसे भारत के कुछ पुराने कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए INICET (राष्ट्रीय महत्व संस्थान सामान्य प्रवेश परीक्षा) आयोजित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली पीजी पाठ्यक्रमों जैसे मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस), डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी), मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस), डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। हर वर्ष करीब 2 लाख छात्र NEET PG और INICET देते हैं। सफल होने वाले छात्रों को 60,000 PG सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। वहीं, पीजी के बाद सर्जरी आदि में स्पेशलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स नीट एसएस आदि का एग्जाम दे सकते हैं।

सैलरी

MBBS, एमडी और सुपरस्पेशियलिटी के डॉक्टरों को लाखों रुपये की सैलरी दी जाती है। हालांकि, प्रैक्टिस के लिए उन्हें FMGE का एग्जाम देना होता है। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है।



एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर के रूप में चुनें करियर

यदि आप आसमानी ट्रैफ़िक को सुरक्षित रखने में रुचि रखते हैं और हवाई यातायात की गति पर नज़र रखने का चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी के रूप में करियर विकल्प चुन सकते हैं। एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी टकराव को रोकने के लिए और यातायात की भीड़ से उत्पन्न होने वाली देरी को कम करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुसार हवाई अड्डे के आसपास और भीतर हवाई यातायात को नियंत्रित करते हैं।

एक हवाई यातायात नियंत्रक हवाई यातायात के सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल आवागमन के लिए और हवाई अड्डों के आसपास के क्षेत्र में जिम्मेदार होता है। नियंत्रकों के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन वे विमानों को भी आसानी से निर्देशित करते हैं ताकि देरी को कम किया जा सके, नामित हवाई अड्डों के माध्यम से हवाई अड्डे के यातायात को विनियमित किया जा सके और हवाई अड्डे के आगमन और प्रस्थान को विनियमित किया जा सके।

बहुत व्यस्त हवाई अड्डों में, हवा नियंत्रकों और जमीन नियंत्रकों के बीच काम विभाजित है। लैंडिंग के दौरान एयर नियंत्रक विमान का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि ग्राउंड कंट्रोलर रनवे पर विमानों का प्रबंधन करते हैं, पार्किंग स्टैंड और होल्डिंग क्षेत्रों से विमानों को टैक्सी के रूप में निर्देश जारी करते हैं।

वायु यातायात नियंत्रकों की भूमिका

- आने और प्रस्थान करने वाले विमानों से रेडियो कॉल करना।
- लैंडिंग और टेक-ऑफ निर्देश और सूचना जारी करना।
- टेलीफोन या अंतर-फोन का उपयोग करके, हवाई यातायात नियंत्रण केंद्र से आने वाली उड़ानों के नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए उड़ानों को स्थानांतरित करने पर नियंत्रण रखना।
- हवाईअड्डे के आपातकालीन कर्मचारियों और अन्य नामित कर्मियों को अलर्ट करते रहना, जब हवाई जहाज को उड़ान में कठिनाई होती है।
- एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी रेडियो का संचालन करता है और हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्र में काम करने वाले विमानों को नियंत्रित करने के लिए रडार की निगरानी करता है।

वायु यातायात नियंत्रकों के कौशल

संचार कौशल - जब पायलट निर्देशों के लिए नियंत्रण टॉवर से संपर्क करते हैं, तो हवाई यातायात नियंत्रकों को उनके अनुरोधों को ध्यान से सुनना चाहिए और स्पष्ट रूप से बोलकर जवाब देना चाहिए।

एकाग्रता कौशल और सतर्कता - वायु यातायात नियंत्रकों के लिए एकाग्रता कौशल और सतर्कता हर समय काम आती है। उन्हें अपने कार्य में एकाग्रता रखनी चाहिए।

निर्णय लेने का कौशल - नियंत्रकों को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। कई बार आपातकालीन स्थिति में उन्हें निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

मल्टीटास्किंग स्किल्स - कंट्रोलर को कई फ्लाइट्स की क्रियाओं को समन्वित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें एक साथ कई कामों को करना आना चाहिए।

समस्या-समाधान कौशल - नियंत्रकों को जटिल परिस्थितियों को समझने और महत्वपूर्ण जानकारी की समीक्षा करने और पायलटों को एक उचित समाधान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

कार्य सारिणी

अधिकांश हवाई यातायात नियंत्रक पूरे समय काम करते हैं, और कुछ को अतिरिक्त घंटे काम करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश नियंत्रण टॉवर और मार्ग केंद्र घड़ी के चारों ओर संचालित होते हैं, नियंत्रक दिन, शाम और रात के बीच पारियों को घुमाते हैं। कंट्रोलर सप्ताहांत और छुट्टी की पाली में भी काम करते हैं।

एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी की करियर संभावनाएं

एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर या एटीसी एयरपोर्ट कंट्रोल ऑपरेटर, कंट्रोल टॉवर रेडियो ऑपरेटर, फ्लाइट कंट्रोल टॉवर ऑपरेटर, एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल स्पेशलिस्ट (एटीसीएस), एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कंट्रोलर (सीपीसी), एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर (एनरूट ऑपशन), एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर (टॉवर ऑपशन) आदि रुपों में काम कर सकते हैं।





बतौर मेकअप आर्टिस्ट बनाएं अपना भविष्य

अगर आप भी खुद को और दूसरों को खूबसूरत बनाने में रूचि रखते हैं तो बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना भविष्य देख सकते हैं।

आज के समय में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, चाहे वह महिला हो या फिर पुरूष। सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग मेकअप पर निर्भर हैं। घर से बाहर शायद ही कोई महिला बिना मेकअप के निकलती है। मेकअप के इस दौर को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, टेलीविजन, फिल्म और फैशन इंडस्ट्री ने। इनके कारण पहले जहां सिर्फ महिलाएं ही मेकअप करती नजर आती थी, वहीं अब पुरूष भी इनसे पीछे नहीं हैं। इन सभी को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट ही वह व्यक्ति होता है जो किसी भी आर्टिस्ट को उसके किरदार में ढालने में एक अहम भूमिका निभाता है।

मेकअप आर्टिस्ट का कार्य

किसी भी चेहरे को सुंदर बनाना मेकअप आर्टिस्ट का मुख्य कार्य होता है। मेकअप आर्टिस्ट यह पता लगाता है कि किसी के चेहरे के अनुसार उस पर कैसा मेकअप सूट करेगा, वो व्यक्ति कैसे सुंदर लगेगा। ये सारा काम मेकअप आर्टिस्ट का होता है। फिल्मों और टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की बहुत सुंदर दिखने लगती है। ये सब मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल होता है। लड़कियों की तरह ही लड़कों का भी मेकअप होता है, जिससे वह ज्यादा स्मार्ट दिखें।

किस तरह का करें कोर्स

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए बुहत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस क्षेत्र में महरत हासिल करने के लिए कोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेकअप किसी व्यक्ति की स्किन से जुड़ा मामला है, आपने कोई प्रॉडक्ट उस व्यक्ति पर लगाया और वो खराब हुआ तो उसकी स्किन हमेशा के लिए खराब हो सकती है। ऐसे में आपको मेकअप आर्टिस्ट से जुड़ा कोर्स जरूर करना चाहिए। जिसमे आप मेकअप और कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट से जुड़ी बारीकियों को समझ सके। इसके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। इसमें दाखिला आप 12वीं के बाद ले सकते हैं। इन कोर्स में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है।

इन स्किल्स की जरूरत

मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपका क्रिएटिव माइंड होना बेहद आवश्यक है, जिससे आप अपने क्लाइंट की पर्सनैलिटी के अनुरूप मेकअप कर पाएं। हर चेहरा एक जैसा नहीं होता। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति क्लाइंट की डिमांड और मौके के हिसाब से परफेक्ट मेकअप कर पाने में सक्षम होता है, उसे इस क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही एक मेकअप आर्टिस्ट को हर स्टाइल और गेटअप के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड के बारे में हमेशा रिसर्च करती रहनी चाहिए।

करियर कहां बनाए

आप इस फील्ड में कई जगह करियर बना सकते हैं। अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम कर प्रतिमाह लाखों रुपए कमा सकते हैं। बड़े- बड़े एक्टर्स को पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट की तलाश होती है। इसके अलावा आप टीवी चैनल, प्रॉडक्शन हाउस, फैशन इंडस्ट्री में नौकरी की तलाश कर सकते हैं। यहां भी मेकअप आर्टिस्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप किसी के अधीन नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद भी मेकअप का काम शुरू कर सकते हैं।

कितनी होगी सैलरी

मेकअप आर्टिस्ट की सैलरी आपके कार्य, कार्य स्थल और अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आप फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और अन्य स्थानों में कार्य कर रहे हैं तो प्रतिमाह लाखों रूपए कमा सकते हैं, वहीं अपना रोजगार शुरू करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं।



12वीं के बाद करें गेम डिजाइनिंग का कोर्स

अगर आप भी 12वीं के बाद किसी ऐसे कोर्स की तलाश में हैं, जहां पर आपके कॅरियर ग्रोथ के साथ अच्छा पैसा कमा सकें। तो बता दें कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक बेहतरीन कॅरियर आप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। बता दें कि इस फील्ड में आने के बाद आपको किस तरह का कॅरियर ग्रोथ मिलेगा। इस फील्ड में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे। ऐसे में अगर आप भी 12वीं के बाद किसी बेहतरीन फील्ड की तलाश में हैं, तो गेमिंग फील्ड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।

वर्तमान समय की बात करें तो देश में गेमिंग इंडस्ट्री में 50,000 से ज्यादा लोग फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। जिसमें से 30 फीसदी लोग प्रोग्रामर और डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं इस फील्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर लाखों की संख्या में जॉब्स पैदा होने की संभावनाएं हैं।

गेम डिजाइनर गेम के कैरेक्टर्स, गेम के लेवल के अलावा तमाम बारीकियों को ध्यान में रखकर उसे इंट्रेस्टिंग बनाने पर फोकस करते हैं। वहीं गेम राइटर डायग्राम आदि बनाकर उसके अलग-अलग वर्जन को तैयार करते हैं। गेम डिजाइनर को टेक्निकल नॉलेज होने के साथ ही सोच में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। गेम तैयार करने के लिए उसकी डिजाइन, डेवलपर्स, आर्टिस्ट्स और अन्य प्रोफेशनल की टीम एक साथ वर्क करती है।

क्वालिफिकेशन

- छात्र ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास किया हो।
- कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी होता है।
- गेम डिजाइनर बनने के लिए आपकी इंग्लिश भाषा पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है।
- इस फील्ड में आप गेम डिजाइनिंग, गेम डेवलपिंग, आर्ट, एनिमेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इलस्ट्रेशन या मार्केटिंग में बैचलर डिग्री या पेशेवर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं।

जरूरी स्किल्स

- गेमिंग फील्ड में कॅरियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के पास कैरेक्टर डिजाइन, एनिमेशन, कांसेप्ट आर्ट और विजुअल इफेक्ट की जानकारी होनी चाहिए।
- इस फील्ड में 2 डी गेम डेवलपर्स, 3 डी गेम डेवलपर्स और जावा आदि में अपार संभावनाएं हैं।
- इस फील्ड में डिजाइनिंग के साथ 2डी सॉफ्टवेयर और 3डी मॉड्यूलिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
- ऑडियो इंजीनियर के लिए युवाओं के पास साउंड इंजीनियरिंग और अन्य लैंग्वेज की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

जॉब प्रोफाइल

इस फील्ड में युवा एनिमेटर, क्यूएक टेस्टर, ऑडियो इंजीनियर, गेम डिजाइनर, गेम डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोड्यूसर, मैनेजर्स, कास्टर्स, ईस्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, स्ट्रीमर्स, इंफ्यूएंसर्स के तौर पर अपना कॅरियर बना सकते हैं।

न्यूज डायरी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 6 कर्मचारी यूनियनों के साथ की बैठक; जायज़ मांगों के निपटारे के लिए विभागों को दिए निर्देश

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। कर्मचारी मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के रूप में वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने आज 6 कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान कर्मचारियों की लंबित मांगों और उनके सामने आ रही कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को सभी जायज़ मांगों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके मुद्दों के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है।

इस विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया कि वे सभी जायज़ मांगों की गंभीरता से जांच करें और उनका जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करें।

कर्मचारी कल्याण के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया, 'राज्य सरकार आपके मुद्दों के समाधान के लिए पहले से ही सहानुभूति और सद्भावना के साथ काम कर रही है।'

वित्त मंत्री ने एसोसिएट प्री-प्राइमरी टीचर यूनियन पंजाब, स्पेशल कैडर टीचर फ्रंट पंजाब और फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की और उनके मांग-पत्र प्राप्त किए। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी क्लीनिक साझा फ्रंट पंजाब, आउटसोर्स स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी यूनियन पंजाब और पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स के प्रतिनिधियों की मांगें भी ध्यानपूर्वक सुनीं।

स्पीकर संधवां ने पंजाब सरकार की 'मेरा घर मेरे नाम' योजना के तहत गांव हरी नौं के निवासियों को संपत्ति के मालिकाना हक सौंपे



चंडीगढ़- पंजाब विधान सभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां ने आज जिला फरीदकोट की तहसील कोटकपूरा के गांव हरी नौं के निवासियों को पंजाब सरकार की 'मेरा घर मेरे नाम' योजना के अंतर्गत घरों के मालिकाना हक सौंपे।

समारोह के दौरान स्पीकर संधवां ने 'लाल लकीर/लाल डोरे' (गांव की आबादी देह) के अंदर रहने वाले लोगों को संपत्ति के मालिकाना हक प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह योजना अपने घर में लंबे समय से रह रहे निवासियों को कानूनी मान्यता देती है, जिससे उनके संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे, भूमि विवाद कम होंगे और वे बैंकों से आसानी से ऋण भी ले सकेंगे।

इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय नेता और गांव के निवासी उपस्थित थे। लाभार्थियों ने अपनी संपत्तियों के मालिकाना हक सुरक्षित करने और लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया।

अमन अरोड़ा ने 'पंजाब इन्वेस्टर सर्कल 2.0' का किया शुभारंभ; 28 स्टार्टअप को 1.17 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट वितरित

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब में अनुसंधान और नवाचार आधारित विकास को नई गति प्रदान करते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने 'पंजाब इन्वेस्टर सर्कल' के पहले संस्करण की शुरुआत के महज चार महीने के भीतर आज इसके दूसरे संस्करण 'पंजाब इन्वेस्टर सर्कल 2.0' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए 28 स्टार्टअप को 1.17 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट भी वितरित की।

यहां एक होटल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब अब आईटी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं जीव विज्ञान, कृषि, खाद्य एवं पेय पदार्थों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है। इनमें से 50 प्रतिशत स्टार्टअप का नेतृत्व महिला निदेशकों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई में आईएनएसटी मोहाली में इस मंच की शुरुआत की गई थी और केवल चार महीने में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्टार्टअप और निवेश पूंजी के बीच निरंतर समन्वय स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

उद्यमियों को बधाई देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि पंजाब में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2021-22 के 36 से बढ़कर वर्ष 2026 में 404 हो गई है। अब तक 222 स्टार्टअप को 6.80 करोड़ रुपये की सीड फंडिंग दी जा चुकी है। एसआरएफ 4.0 और 5.0 में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहचान बनाने के बाद पंजाब ने 'पंजाब स्टार्टअप नीति-2026' के माध्यम से अपने प्रोत्साहन ढांचे को और मजबूत किया है। इस नीति के तहत दो किस्तों में 15 लाख रुपये तक की सीड ग्रांट, ब्याज एवं लीज किराये पर सब्सिडी तथा सरकारी खरीद में प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 350 से अधिक आउटरीच गतिविधियों, पंजाब इन्वेस्टर सर्कल और स्टार्टअप पंजाब हब-न्यूरॉन 2.0 के माध्यम से राज्य में वित्तपोषण, इनक्यूबेशन और औद्योगिक साझेदारी का मजबूत तंत्र विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं में उद्यमशीलता की अपार क्षमता है। राज्य सरकार उनके नवाचारपूर्ण विचारों को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता, संस्थागत सहयोग, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दे रही है।

भगवंत मान सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री खुरालगढ़ साहिब में करवाया जाएगा 3 दिवसीय विशाल समागम: हरपाल सिंह चीमा

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे धार्मिक वैभव और श्रद्धा के साथ मनाने संबंधी भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करके पवित्र अस्थान श्री खुरालगढ़ साहिब में होने वाले तीन दिवसीय विशाल समागमों की तैयारियों का जायजा लिया।



श्री खुरालगढ़ साहिब में होने वाले ऐतिहासिक धार्मिक इकट्ठ की महत्वता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा, '4 से 6 दिसंबर तक चलने वाला यह तीन दिवसीय कार्यक्रम भगवंत मान सरकार द्वारा करवाए जा रहे समागमों का मुख्य आकर्षण होगा।' उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि पंजाब और देश भर से आने वाली संगत के लिए यह समागम अधिक सुचारू, आध्यात्मिकता से भरपूर और यादगार साबित हो।

बैठक दौरान वित्त मंत्री ने मुख्य दीवान, धार्मिक रीति-रिवाजों, बुनियादी ढांचे, सफाई, आवाजाही, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, पीने के पानी और संगत की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक प्रबंधों के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की।

श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन और दर्शन में श्री खुरालगढ़ साहिब की अहमियत के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'श्री खुरालगढ़ साहिब में तीन दिवसीय समागम 650वें प्रकाश पर्व समागमों का मुख्य आकर्षण होंगे।' उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य इस ऐतिहासिक अवसर पर गुरु साहिब के बराबरी, मानवीय मान-सम्मान, सामाजिक सद्भावना और विश्व-व्यापी भाईचारक सांझ के सदैव दर्शन को सच्ची श्रद्धांजलि देना है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया, 'समागमों की श्रृंखला के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों से सजाई जा रही चार प्रमुख शोभा यात्राएं 3 दिसंबर को श्री खुरालगढ़ साहिब में समाप्त होंगी, जिससे देश भर से संगतें मुख्य धार्मिक कार्यक्रम से पहले यहां पहुंच जाएंगी।'

उन्होंने कहा, 'यह शोभा यात्राएं श्री गुरु रविदास जी महाराज के सर्व-सांझे संदेश और पवित्र शिक्षाओं के प्रसार का अहम जरिया बनेंगी और इस ऐतिहासिक अवसर से पहले श्रद्धा, एकता और आपसी सांझ का आध्यात्मिक माहौल सृजित करेंगी।'

धार्मिक कार्यक्रमों के विवरण साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री स. हरपाल सिंह चीमा ने बताया, '4 दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होंगे, जिनके भोग 6 दिसंबर को पाए जाएंगे, जिसके साथ ही श्री खुरालगढ़ साहिब में तीन दिवसीय समागमों की समाप्ति होगी।'

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी प्रबंध अग्रिम रूप से पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संगत, विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों, जो इस पवित्र अस्थान पर आएंगे, उनकी सुविधा और आराम का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच को दोहराते हुए चीमा ने कहा, 'पंजाब सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पहलों के माध्यम से श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।'

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने निराधार दावों को लेकर चरनजीत सिंह चन्नी की कड़ी आलोचना की; भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में लॉटरी राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि का दिया हवाला

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां राज्य में लॉटरी संचालन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता चरनजीत सिंह चन्नी के हालिया बयानों का कड़ा खंडन करते हुए उनके दावों को निराधार, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने का हताश प्रयास करार दिया।



विस्तृत तथ्य एवं आंकड़े जारी करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'ये आंकड़े पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल में हासिल हुई अभूतपूर्व पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि को भी दर्शाते हैं।'

पंजाब में कांग्रेस और 'आप' सरकारों के बीच स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, 'चरनजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य की लॉटरी से शुद्ध प्राप्तियां मात्र 19.33 करोड़ रुपये थीं, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 32.77 करोड़ रुपये पर ठहरा हुआ था। इसके विपरीत, भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शुद्ध प्राप्तियां बढ़कर रिकॉर्ड 70.59 करोड़ रुपये हो गईं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भी 31 अक्टूबर तक राज्य पहले ही 54.21 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अर्जित कर चुका है।'

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, 'इसके अतिरिक्त, राज्य ने लॉटरी से जीएसटी संग्रह में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग तीन गुना हो गया है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2021-22 के 32.77 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 93.09 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2026 तक जीएसटी संग्रह 59.43 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।'

त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरी पर कड़ी नजर: 110 क्विंटल असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त, 50 क्विंटल मिलावटी दूध उत्पाद नष्ट किए गए

चंडीगढ़- त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पंजाब के खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर निगरानी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान चलाया हुआ है।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल के सख्त निर्देशों पर विशेष टीमें राज्य के सभी 23 जिलों में निर्माण इकाइयों, थोक मंडियों, मिठाई की दुकानों, डेयरियों, रेस्टोरेंटों और खुदरा दुकानों पर दिन-रात जांच कर रही हैं।



राज्य सरकार के इस सख्त रुख का उल्लेख करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उन लोगों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है, जो मामूली व्यावसायिक लाभ के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, ''त्योहार खुशी और उत्सव का समय होते हैं और हर घर तक मिलावट रहित एवं पौष्टिक भोजन पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। मिलावटखोरी, नकली वस्तुओं का निर्माण करने या घटिया स्तर के खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006' के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।''

राज्यभर में चलाए जा रहे इस अभियान की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले एक महीने के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के दिनों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं, जैसे देसी घी, दूध, पनीर, खोया, पारंपरिक मिठाइयों, खाद्य तेलों, वनस्पति और मसालों पर विशेष रूप से कड़ी नजर रखी है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पी.सी.एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ की बैठक

पी.सी.एस. अधिकारियों के कैडर से जुड़े मुद्दों और लंबित मांगों का प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा समाधान: हरपाल सिंह चीमा



हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उनके कैडर से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों और बकाया मांगों पर विचार-विमर्श किया। एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए मांग-पत्र पर विस्तृत चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने ऑफिसर्स कमेटी को सभी प्रस्तुतियों की बारीकी से जांच करने और इनके समयबद्ध समाधान के लिए जल्द से जल्द एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान पी.सी.एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक औपचारिक मांग-पत्र सौंपा, जिसमें कैडर को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक मुद्दे उठाए गए। अपनी प्रमुख वित्तीय मांगों में एसोसिएशन ने आई.ए.एस. और पी.सी.एस. (न्यायिक) अधिकारियों के साथ पहले की तरह वेतन समानता बहाल करने तथा मौजूदा विसंगति (एनोमली) को दूर करने की मांग की, जिसके कारण उनके प्रवेश स्तर के वेतनमान को घटाकर लेवल-9 कर दिया गया है। एसोसिएशन ने प्रारंभिक वेतनमान (एंट्री-लेवल पे स्केल) को दोबारा 56,100 रुपये करने की मांग रखी।

एसोसिएशन ने परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) के दौरान प्रारंभिक नियुक्तियों को बिना भत्तों के केवल मूल वेतन तक सीमित रखने संबंधी निर्देशों को वापस लेने और प्रभावित बैचों को पिछली तिथि से बकाया राशि देने की मांग भी की। इसके अतिरिक्त, कैडर में लंबे समय से चली आ रही ठहराव की स्थिति को दूर करने के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) योजना बहाल करने के साथ-साथ छठे पंजाब वेतन आयोग के बकाये और महंगाई भत्ते (डी.ए.) का बकाया तुरंत जारी करने पर जोर दिया गया।

कैडर प्रबंधन और पदोन्नति के अवसरों के संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से अपील की कि पी.सी.एस. अधिकारियों को समय पर आई.ए.एस. कैडर में पदोन्नत करने के लिए एक सुचारू व्यवस्था स्थापित की जाए तथा पदोन्नतियों से संबंधित बैकलॉग को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष भर्ती का एक निश्चित कैलेंडर लागू किया जाए। मेमोरेंडम में पी.सी.एस. कैडर के लिए पदोन्नति के अवसर सुरक्षित रखने हेतु गैर-राज्य सिविल सेवा (नॉन-स्टेट सिविल सर्विसेज) अधिकारियों की आई.ए.एस. में वैकल्पिक नियुक्तियों को नियमित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। एसोसिएशन ने आंतरिक पदोन्नतियों के लिए पात्रता संबंधी सेवा वर्षों में स्वीकृत छूट के नोटिफिकेशन तत्काल जारी करने के साथ-साथ निर्धारित विभागीय एवं विभागाध्यक्ष के पदों पर पी.सी.एस. अधिकारियों की उचित तैनाती की भी मांग की।

एसोसिएशन ने पी.सी.एस. (ई.बी.) सेवा नियमों की समीक्षा कर रही कमेटी में वरिष्ठ पी.सी.एस. अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैडर के व्यापक हितों की सही ढंग से रक्षा हो सके।

राज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण, युवा विकास और नशामुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया

हिन्द जनपथ

शिमला (ब्यूरो)। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज बिलासपुर में लाडली फाउंडेशन द्वारा आयोजित भारतीय उत्कृष्टता पुरस्कार-2026 समारोह में एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया, जहां हर बेटी को समान अवसर मिलें, हर महिला सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सके व हर युवा आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सके।



उन्होंने इस आयोजन के लिए फाउंडेशन की सराहना की तथा समाज और राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वाले सम्मानित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को शुभकामनाएं दीं।

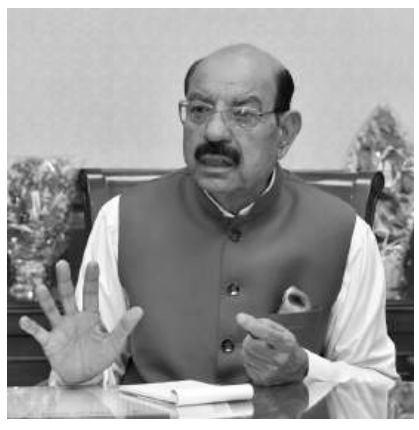
राज्यपाल ने कहा कि किसी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि महिलाओं को मिलने वाले सम्मान और सुरक्षा, बेटियों के लिए उपलब्ध अवसरों, युवाओं की जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता तथा कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता से भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि लाडली फाउंडेशन द्वारा इन क्षेत्रों में किया जा रहा कार्य सामाजिक कल्याण के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के स्थान का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को परंपरागत रूप से शक्ति, सृजनशीलता और संस्कारों का प्रतीक माना गया है। आज भारतीय महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, रक्षा, उद्यमिता और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक बेटी को शिक्षा, सुरक्षा, समान अवसर और आत्मनिर्भर बनने के साधन उपलब्ध हों।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का आंदोलन है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पंजाब सरकार के सहयोग से 13 से 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा 10वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल : मोहिंदर भगत

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज विभाग की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए 13 से 15 नवंबर, 2026 तक चंडीगढ़ के सेक्टर 5 स्थित लेक क्लब में होने वाले 10वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की तैयारियों और प्रबंधों का जायजा लिया।



बैठक के दौरान मंत्री ने पूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को उनके कल्याण संबंधी मामलों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड और भाग लेने वाली अन्य संस्थाओं के सहयोग से करवाए जा रहे इस प्रतिष्ठित आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत की गौरवशाली सैन्य विरासत, सशस्त्र बलों की वीरता और देश की सेवा में सैनिकों द्वारा दिए गए महान बलिदानों को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। 'पंजाब और भारत के युवाओं की सेवा का एक दशक' विषय पर आधारित इस आयोजन के 10वें संस्करण में कई जानकारीपूर्ण, शैक्षिक और रोचक गतिविधियां शामिल होंगी। यह आयोजन आम लोगों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मंत्री ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को देश के महान सैन्य इतिहास से जोड़ना और उन्हें साहस, देशभक्ति, नेतृत्व और बलिदान की कहानियों के माध्यम से प्रेरित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 10वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं, पूर्व सैनिकों, रक्षा मामलों में रुचि रखने वालों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा।

मान सरकार ने 1,325 करोड़ रुपये खर्च कर किसानों को उपलब्ध करवाईं 94,456 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें: गुरमीत सिंह खुड्डियां

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पराली प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 1,325.35 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया है। इसके परिणामस्वरूप अब राज्य में 94,456 फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनें उपलब्ध हैं और पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2022 में पराली जलाने के 49,922 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर मात्र 5,114 रह गए।



पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों के आंकड़े जारी करते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि सरकार इस अभियान में कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए किसानों ने लगभग 201 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाते हुए 22,763 सीआरएम मशीनें खरीद ली हैं। इससे पंजाब पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पिछले वर्ष किसानों को उपलब्ध करवाई गईं 13,147 मशीनों की तुलना में 67 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

स. खुड्डियां ने कहा, 'मुख्यमंत्री मान के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी किसान पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीके अपनाने से वंचित न रहे।'

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 से अब तक 1,325 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके 94 हजार से अधिक सीआरएम मशीनें उपलब्ध करवाना पंजाब की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अभियान का वर्षवार विवरण देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान 27,250 मशीनों के लिए 279.96 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 13,179 मशीनों के लिए 168.88 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 18,117 मशीनों के लिए 259.81 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 के दौरान 13,147 मशीनों के लिए 415.7 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई। पराली जलाने के खिलाफ पंजाब सरकार की शून्य-सहनशीलता नीति दोहराते हुए कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही पराली प्रबंधन मशीनरी का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए 22 हजार से अधिक मशीनों की समय पर खरीद से यह सुनिश्चित हुआ है कि पंजाब इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे किसानों को पराली जलाए बिना उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने में और अधिक सहायता मिलेगी।

पंजाब पुलिस ने प्रदेश के 214 बस अड्डों पर चलाया तलाशी अभियान

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार दिवाली का त्योहार प्रदेशभर में सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाना सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने आज राज्य के 214 बस अड्डों पर घेराबंदी एवं तलाशी अभियान (कासो) चलाया।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देशों पर यह अभियान प्रदेश के सभी 28 पुलिस जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक साथ चलाया गया।

विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण सिन्हा, जो स्वयं इस राज्यव्यापी अभियान की निगरानी कर रहे थे, ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पुलिस आयुक्तों (सीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए थे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के बस अड्डों पर चलाए गए इस अभियान के दौरान 1,161 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई।

विशेष डीजीपी ने बताया कि 100 से अधिक राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 1,500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 216 पुलिस टीमों ने प्रदेशभर में यह कार्रवाई की।

इसके अतिरिक्त, पुलिस टीमों ने 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के 613वें दिन आज 301 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान प्रदेशभर में 86 एफआईआर दर्ज कर 112 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

उत्तर रेलवे

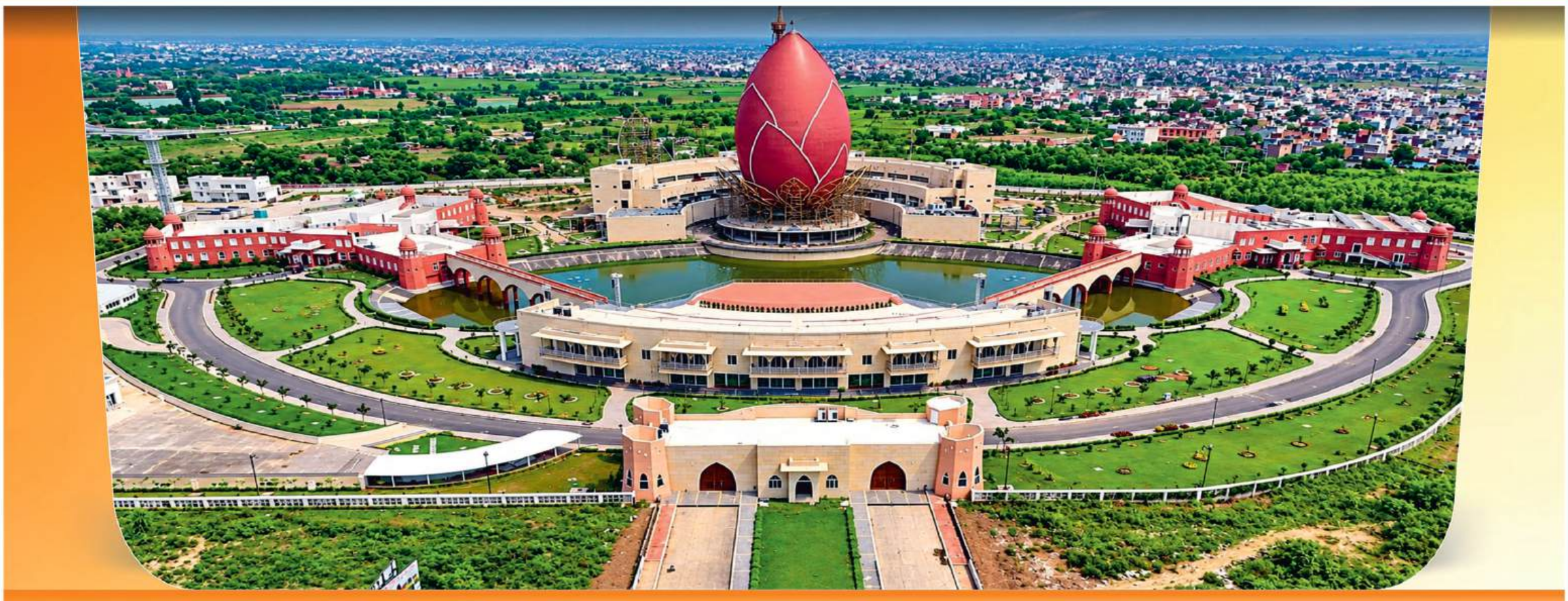
ई–निविदा सूचना

वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (आई/ सी) उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशॉप, यमुनानगर, हरियाणा-135002, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, केवल निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से ई–निविदाएं आमंत्रित करता है:–

कार्य का नाम	LHB EOG AC कोचों में उच्च क्षमता वाले कपलर और फीडर केबलों का प्रावधान।		
निविदा प्रकार	खुला	बोली प्रणाली	एकल पैकेट प्रणाली
निविदा विक्रय समापन तिथि	25.11.2026 प्रातः 11.30 बजे	निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय	02.11.2026
पूर्व–बोली आवश्यक है।	नहीं	आज तक प्री–बिड क्वेरी	ना
विज्ञापन मूल्य	₹6,06,27,615.30/- सभी कर जीएसटी आदि सहित।	निविदा अनुभाग	टेंडर एवं वर्क्स/ इलेक्ट्रिकल शाखा जगाधरी वर्कशॉप
अग्रिम धन	₹12,12,600/-	ऑफर की वैधता	60 दिन
निविदा दस्तावेज लागत	Nil अप्रैल 2022 के भाग-I खंड संख्या 3 के अनुसार	समापन की अवधि	24 माह
बोली आरंभ तिथि	11.11.2026	बोली समाप्ति तिथि	25.11.2026 प्रातः 11.30 बजे
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	उसके बाद किसी भी समय निविदा को बंद किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। निविदा बंद होने के बाद किसी भी समय निविदा खोलने का अधिकार रेलवे के पास सुरक्षित है।		
वेबसाइट	www.ireps.gov.in पर जाएं		

सं. -56/W/Elect/25-26/T/19/ कप्लर और फीडर केबल/ आर टी दिनांक: 02.11.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3843/2026



हरियाणा सरकार | हरियाणा हीरक जयंती HARYANA HIRAK JAYANTI 1966 - 2026 | आजादी की पहली लड़ाई (1857) का शहीद स्मारक

"आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे-बेटियों का त्याग, बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण है।"

- नरेन्द्र मोदी



आजादी के प्रथम संघर्ष (1857) को समर्पित

शहीद स्मारक का लोकार्पण

5 नवम्बर, 2026 | दोपहर 3:00 बजे

शहीद स्मारक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44, अम्बाला कैंट

मुख्य अतिथि

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

अध्यक्षता

श्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री, हरियाणा

अन्य कार्यक्रम

जनसभा

समय - सायं 4:00 बजे

स्थान - रैली स्थल, गांधी ग्राउंड, अम्बाला कैंट

जनसभा से जुड़ने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

जलबेहड़ा - शाहाबाद (NH-152G)

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन

आप सादर आमंत्रित हैं

HARYANACMO | CMOHRY | www.haryanacmoffice.gov.in

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा | www.prharyana.gov.in | Follow us on @diprharyana